



पैरा तीरंदाजी में छग को गोल्ड

रायपुर, 8 सितंबर। पैरा वर्ल्ड सीरीज अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 10



सितंबर तक अहमदाबाद में आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में आज छत्तीसगढ़ के तीरंदाज टोमन कुमार ने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उम्मीद है शाम तक एक और मेडल वर्ल्ड आर्चरी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा जी भारतीय तीरंदाजी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका पूरे समय आयोजन में उपस्थित रहे।

अलग-अलग तालाब में मिली दो लाशें

बिलासपुर/कटघोरा, 8 सितंबर। छत्तीसगढ़ के दो जिलों में आज सुबह दो लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बिलासपुर के मुख्य खदान में जहां महिला की लाश मिली, तो वहीं कोरबा के नवकोनिया तालाब में एक युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पेंडारी की मुरुम खदान के तालाब में एक अज्ञात महिला की लाश तैरती हुई मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। साथ ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पाली थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर स्थित नवकोनिया तालाब में मंगलवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की तैरती हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर मामले की जांच शुरू की। शव से दुर्गंध आने के कारण पुलिस ने आशंका जताई है कि व्यक्ति की मौत करीब दो-तीन दिन पहले हुई होगी। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। सबसे अहम बात यह है कि घटनास्थल के पास ही एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली है। पुलिस को आशंका है कि यह बाइक मृतक की हो सकती है।

छात्राओं के पैदल कलेक्टोरेट मार्च पर साथ ने जताई नाराजगी

रायपुर, 8 सितंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिले के शिवपुर एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं के अपनी समस्याओं को लेकर पैदल कलेक्टोरेट के लिए निकलने की घटना को गंभीरता से लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में लंबे समय से समस्याएं बने रहने और छात्राओं को अपनी बात रखने के लिए इस तरह पैदल निकलने की स्थिति उत्पन्न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर से कहा कि बच्चियों को अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय से पैदल निकलना पड़े, यह स्थिति किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है।

तरुण छत्तीसगढ़

आम आदमी का अपना दैनिक अखबार

■ रायपुर, मंगलवार 08 सितंबर 2026 ■ भाद्रपद कृष्ण पक्ष-10 ■ वर्ष -42 ■ अंक-160 ■ पृष्ठ 8 ■ डाक संस्करण 09 सितंबर 2026 ■ मूल्य-2.00 रुपये

पीएम मोदी ने आधी रात मंत्रियों के साथ की 3 घंटे बैठक

मंत्रालयों के परफार्मेंस का आकलन किया

नई दिल्ली, 8 सितंबर। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की आहट शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आधी रात 12 से अधिक केंद्रीय राज्यमंत्रियों के साथ 3 घंटे बैठक की। ये सभी मंत्री स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे हैं। तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन बैठक में मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों के कामकाज की जानकारी प्रधानमंत्री को दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों के परफार्मेंस का आकलन किया। आगामी हफ्तों में राज्य मंत्रियों के साथ और भी बैठकें होंगी। इनको मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि ऐसी बैठकों से PM राज्यमंत्रियों की परफार्मेंस का भी आकलन कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने टाइम-बाउंड डिलीवरी पर जोर

दिया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं और योजनाओं को तय समय में पूरा किया जाना



चाहिए। काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखें।

यह भी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का फायदा लाभार्थियों तक सीधे पहुंचे। वहीं मंत्रियों ने अब तक किए गए सुधारों और नई पहलों के बारे में

बताया। उन्होंने अपने मंत्रालय की योजनाओं और काम की प्रगति की भी जानकारी दी।



बैठक में सरकार की योजनाओं को जमीन पर तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। बैठक में विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी प्रमुख मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से उनके मंत्रालय के विजन के बारे में पूछा। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश

बनाने के लिए उनके मंत्रालय की क्या योजनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मंत्रालयों का काम विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर होना चाहिए। हर काम में समय की पाबंदी, गुणवत्ता और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मंत्रालयों को अपनी योजनाओं और कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, यह इस तरह की पहली बैठक थी। इसमें कैबिनेट मंत्री या शीर्ष नौकरशाह शामिल नहीं हुए। बैठक में स्वतंत्र प्रभार और अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़े राज्यमंत्री मौजूद रहे। कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े राज्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया।

बिना अनुमति न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग

सोशल मीडिया पर शेयर करने पर अंतरिम रोक

बिलासपुर, 8 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया अथवा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना पूर्व अनुमति प्रसारित, अपलोड, पोस्ट, री-पोस्ट, मैनटेइज या संग्रहित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने

के प्रभाव तथा इसकी व्यवहारिकता की जानकारी भी देने को कहा गया है। अंतरिम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अथवा संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति के उपयोग, प्रसार, अपलोड, ट्रांसमिट, संशोधित, स्टोर या होस्ट नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश 24 जुलाई 2026 को हर्षिता ग्रीवर की रिट याचिका की



सुनवाई के दौरान पारित किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस अंतरिम आदेश सभी संबंधित हाईकोर्ट को निर्देशित किया कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रसारित लाइव स्ट्रीमिंग और कोर्ट कार्यवाही की रिकॉर्डिंग से संबंधित मॉडल नियमों को अपनाने की स्थिति पर स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में लगातार और निर्बाध लाइव स्ट्रीमिंग

के रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति के उपयोग, प्रसार, अपलोड, ट्रांसमिट, संशोधित, स्टोर या होस्ट नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश 24 जुलाई 2026 को हर्षिता ग्रीवर की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस अंतरिम आदेश सभी संबंधित हाईकोर्ट को निर्देशित किया कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रसारित लाइव स्ट्रीमिंग और कोर्ट कार्यवाही की रिकॉर्डिंग से संबंधित मॉडल नियमों को अपनाने की स्थिति पर स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में लगातार और निर्बाध लाइव स्ट्रीमिंग

बुरे फंसे राहुल गांधी

'चौकीदार चोर' वाला केस रद्द करने से हाईकोर्ट का साफ इंकार

नई दिल्ली, 8 सितंबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर 'चौकीदार चोर' है 'चोरों के सरदार' और 'कमांडर-इन-थीफ' कहने वाली टिप्पणी से जुड़ा है। कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।

राहुल गांधी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कथित बयान में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था और न ही किसी 'पहचाने जा सकने वाले या निश्चित वर्ग' को निशाना बनाया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नितिन बोरकर की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी एक पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इसलिए वह निश्चित रूप से एक पहचान योग्य संस्था है। कोर्ट ने

कहा कि शिकायतकर्ता का दावा है कि वह दो दशक से बीजेपी का सक्रिय सदस्य रहा है। पहली नजर में प्रधानमंत्री को, जो बीजेपी के सदस्य हैं, 'कमांडर-इन-थीफ' बताने



वाले बयान को सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तक सीमित नहीं माना जा सकता। कोर्ट के मुताबिक, इस बयान का वास्तविक आशय क्या था और इसका पार्टी के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह सवाल मुकदमे के दौरान विचार किया जाना है। यह शिकायत बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रमल ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दायर की थी। मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी

की टिप्पणी प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के साथ-साथ सत्तारूढ़ पार्टी और उसके सदस्यों तक भी जाती है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उनका दावा था कि नरेंद्र मोदी को 'चोरों के सरदार' कहने से बीजेपी के सभी सदस्यों को 'चोर' के रूप में पेश किया गया। इसी आधार पर उन्होंने मानहानि की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होने की दलील दी। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप पासबोला ने हाईकोर्ट में दलील दी कि कथित ट्वीट में राहुल गांधी ने बीजेपी या किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि किसी 'पहचाने जा सकने वाले या निश्चित वर्ग' को निशाना नहीं बनाया गया है। ऐसे में कोई स्पष्ट रूप से पीड़ित व्यक्ति या समूह मौजूद नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता के पास आपराधिक मानहानि का मामला चलाने का आधार नहीं है। राहुल गांधी की याचिका का महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल डॉ. मिलिंद साठे ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह देखना होगा कि मानहानि के अपराध के लिए जरूरी तत्व मौजूद हैं।

कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, दो घंटे चक्काजाम

राजिम/कोरबा, 8 सितंबर। छत्तीसगढ़ में सोमवार देर रात हुए दो सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि राजिम में सीमेंट से भरा ट्रक पुलिया के पास पलट गया। कोरबा में अज्ञात कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौके



राजिम के फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग पर ग्राम भेंदरी की पुलिया के पास सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया।

पर ही मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस फरार वाहन चालकों की तलाश कर रही है। राजिम के फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग पर ग्राम भेंदरी की पुलिया के पास सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर फिंगेश्वर पुलिस पहुंची और जांच शुरू

की। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया में रेलिंग नहीं होने से यहां हादसों का खतरा बना रहता है। पहले भी कई वाहन पुलिया से नीचे गिर चुके हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से उनके मंत्रालय के विजन के बारे में पूछा। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश

हादसे के बाद ग्रामीणों ने करीब दो घंटे तक सड़क जाम कर दिया। उन्होंने

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी

धमतरी, 8 सितंबर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शेयर ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। वेल्थ ट्रेकर कंपनी के संचालक पर 25 लाख की ठगी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि कलेक्टोरेट के पास 'वेल्थ ट्रेकर' नाम से कंपनी संचालित करने वाले विक्रम सिंह शाह ने शेयर मार्केट में निवेश कर काम समय में ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद प्रार्थी से अलग-अलग किस्तों में 25 लाख रुपये लिए गए। आरोप है कि रकम लेने के बाद जब प्रार्थी ने अपने निवेश

की राशि और कथित मुनाफे की मांग की, तो उसे रकम वापस नहीं मिली। इसके बाद प्रार्थी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस कंपनी से जुड़े लेन-देन, निवेश संबंधी दस्तावेज और रकम के ट्रांजेक्शन की जांच कर सकती है। वहीं, इस मामले में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के लेन-देन और अन्य निवेशकों से भी रकम लिए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कुल कितनी रकम की ठगी हुई है और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

अमेरिका में नौकरीपेशा वालों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना मुश्किल

वाशिंगटन, 8 सितंबर। अमेरिका से भारतीयों के लिए बुरी खबर आई है। EB-1 कैटेगरी के तहत अमेरिकी ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हजारों भारतीयों को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि ज्यादा मांग



के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना मुश्किल हो सकता है। US स्टेट डिपार्टमेंट की यह चेतावनी सितंबर के वीजा बुलेटिन में आई है। बता दें कि ग्रीन कार्ड उन खास लोगों के लिए होता है, जिनमें असाधारण कौशलियत होता है। जैसे कि प्रोफेसर, रिसर्चर, मल्टीनेशनल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर। बुलेटिन के अनुसार 30 सितंबर को

अमेरिका का फाइनेंशियल इंयर खत्म होने से पहले ही भारत के लिए तय EB-1 कोटा खत्म हो सकता है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि EB-1 वीजा कैटेगरी में भारत से जुड़े विदेशी नागरिकों की ज्यादा मांग और वीजा के इस्तेमाल की वजह से आने वाले हफ्तों में इस कैटेगरी को बंद करना पड़ सकता है। अगर फाइनेंशियल इंयर खत्म होने से पहले ही EB-1 कैटेगरी में भारत की तय सीमा पूरी हो जाती है। इस स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट (INA) की धारा 201 की शर्तों के तहत दुनियाभर में रोजगार-आधारित प्राथमिकता सीमा 186,317 है। प्रति-देश सीमा कुल वार्षिक रोजगार सीमा का 7 प्रतिशत तय की गई है, जो कि 28,862 है।

छत्तीसगढ़ के 10 अस्पतालों को मिला 'ईट राइट' टैग

3 प्रतिष्ठान को हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेशन

रायपुर, 8 सितंबर। छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए 'ईट राइट इंडिया' पहल के तहत लगातार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रमाणन, प्रशिक्षण, जागरूकता और प्रवर्तन गतिविधियों के जरिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 10 अस्पतालों को ईट राइट टैग मिला है। वहीं खैरागढ़ के तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग प्रमाणन मिला है। इस प्रमाणन का उद्देश्य खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों के पालन को बढ़ावा देना है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों और बेहतर खाद्य प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए बलरामपुर, कोरबा, महासमुंद, कोरिया, धमतरी, सरगुजा, मनेंद्रगढ़ और रायपुर सहित विभिन्न जिलों में FoSTaC प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

लगातार उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। ईट राइट कैम्पस प्रमाणन के तहत जिला अस्पताल कांकेर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, मुंगेली, राजनांदगांव और बीजापुर के साथ SSIMS Hospital दुर्ग को 'ईट राइट' टैग दिया गया है। इसी तरह खैरागढ़ के तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग प्रमाणन मिला है। इस प्रमाणन का उद्देश्य खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों के पालन को बढ़ावा देना है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों और बेहतर खाद्य प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए बलरामपुर, कोरबा, महासमुंद, कोरिया, धमतरी, सरगुजा, मनेंद्रगढ़ और रायपुर सहित विभिन्न जिलों में FoSTaC प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

अब नाराज फूफा को काम मिल गया: मोदी

गांधीनगर, 8 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ने वडोदरा में 35 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद विपक्ष पर जमकर निशाना साधा नाम लिए बिना उन्हें नाराज फूफा बताया। उन्होंने फ्रेंट कारिडोर को विकसित भारत की जीवन रेखा बताते हुए इसके कई फायदे गिनाए। उन्होंने डबल डेकर मालगाड़ी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा इससे 250 से ज्यादा ट्रकों के बराबर का सामान एक बार में चला गया लेकिन अब नाराज फूफा को चिल्लाने का मौका मिल गया है।

पीएम मोदी ने कहा, ये फ्रेंट कारिडोर एक और वजह से कामला का है। हाल ही में JNPT पोर्ट मुंबई से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर



मालगाड़ी का संचालन किया गया है। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से ज्यादा ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। लेकिन अब ये जो नाराज फूफा जी हैं, वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहा जाएंगे, उनका क्या होगा? अब इन फूफा जी को काम मिल गया है। पीएम मोदी ने कहा, फ्रेंट

कारिडोर के साथ-साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहां जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भी इस परियोजना के द्वारा रेल से जुड़ रहे हैं। पहले की सरकार में बजट में 1-2 ट्रैनों की घोषणा होती थी और उसके भी सारफर भर ढोल पीटे जाते थे। जबकि आज देश में साल भर

एक के बाद एक नई ट्रेंनें चलाई जा रही हैं। आज भी इस कार्यक्रम में कई नई ट्रेंनें शुरू हुई हैं।

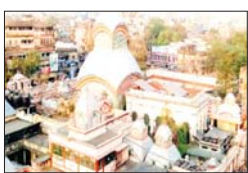
उन्होंने कहा, इस साल का रेल बजट पौने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। ये 12 सालों पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। यानी रेलवे के आधुनिकीकरण पर हो रहा खर्च हजारों-हजार नए रोजगार बना रहा है। उन्होंने कहा, झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर मिल जाएंगे। लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितने फोकस से काम कर रही है।

कोलकाता के कालीघाट मंदिर में

1,000 करोड़ के घोटाले का आरोप

कोलकाता, 8 सितंबर। कोलकाता के सुप्रसिद्ध कालीघाट मंदिर के गहनों की चाबी 1980 से गायब है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से

अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कोलकाता के पुराने जमींदार सबर्ण रॉय चौधरी परिवार ने दक्षिण 24 परगना के जिला जज से संपर्क किया है। दक्षिण 24 परगना के जिला जज



कालीघाट मंदिर समिति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। परिवार के सदस्य सचिव देवर्षी रॉय चौधरी का दावा है कि मंदिर के संबंधित लंबे समय से चले आ रहे सवाल को जवाब अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है। सबर्ण रॉय चौधरी परिवार ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सबर्ण रॉयचौधरी परिवार ने मंदिर के खजाने की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कोर्ट में अर्जी दी है। कोलकाता के ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर को लेकर हाल ही में एक बड़े विवाद में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के संभावित घोटाले और वित्तीय

चौधरी परिवार ने कालीघाट मंदिर से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर अलीपुर जिला न्यायाधीश से संपर्क किया है, जिनमें 1980 से लातपात तिजोरी की चाबी भी शामिल है। जबकि यह तिजोरी एक सरकारी बैंक में रखी है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि मंदिर की संपत्ति का हिसाब रखने वाली समिति का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके चलते वहां लूट मची हुई है।

सेवा संकल्प अभियान एवं समरसता संकल्प अभियान के तहत भाजपा ने किया कलश वितरण

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 8 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के निदेशानुसार प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान एवं गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय सुपेला में कलश वितरण एवं मासिक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला भिलाई संगठन प्रभारी रामजी भारती, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सबनौ तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने की।



इस अवसर पर भूपेंद्र सबनौ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के

25 वर्ष राष्ट्र सेवा, समर्पण और जनकल्याण की प्रेरणादायी यात्रा है। सेवा संकल्प अभियान के

माध्यम से उनके सेवा भाव को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर मिला है। नीलू शर्मा ने कहा कि सेवा के केवल जरूरतमंदों की सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलना भी सेवा का महत्वपूर्ण स्वरूप है। रामजी भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। वहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का जीवन सामाजिक समानता, भाईचारे और समरसता का संदेश देता है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि सेवा और समरसता के माध्यम से ही सशक्त एवं एकजुट समाज का निर्माण संभव है। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कहा कि भाजपा के लिए

सेवा कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन की मूल कार्य संस्कृति है। कार्यक्रम प्रभारी एवं जिला महामंत्री सुषमा जैठानी ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत किया। जिला महामंत्री मनीष अग्रवाल ने कहा कि सेवा से समाज मजबूत होता है और समरसता से समाज एकजुट होता है। बैठक में जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री, विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने सेवा, समर्पण, सामाजिक समरसता, समानता एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मंडल और बृथ स्तर तक पहुंचाने तथा अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।

क्रय एवं क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों पर हुआ विचार-विमर्श



भिलाई, 8 सितम्बर। बीएसपी के सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पूर्व चलाए जा रहे अभियान के तहत मैकेनिकल संगठन के लिए सतर्कता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक एवं अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी सुनील सिंगल तथा मुख्य महाप्रबंधक विवेक वर्मा ने की। संचालन उप महाप्रबंधक मो. नौशाद आलम एवं नवनीत शर्मा ने किया।

एक नजर

गांजा बेचने के आरोप में युवक गिरफ्तार



भिलाई, 8 सितंबर (तछसं)। भिलाई गांजा का अवैध कारोबार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पचनाभपुर टीआई राजेश मिश्रा ने बताया मुखबिर की सूचना पर दुर्ग बस स्टैण्ड स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास अवैध रूप से गांजा बेचने की शिकायत मिली मौके पर पहुंची पचनाभपुर थाने पुलिस ने घेराबंदी कर अंतुले नगर, येवलेबाड़ी, थाना कोल्वा, जिला पुणे, महागढ़ निवासी वसंत श्याम राव ओमकारे को गिरफ्तार किया आरोपी के पास से काले रंग के बैग की तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ कुल 2.520 किलोग्राम गांजा था पुलिस नेकम, मोबाइल फोन जब्त किया है।

32 लाख गबन,कैशियर गिरफ्तार

भिलाई, 8 सितंबर (तछसं)। हाईड्रिक अस्पताल की करीब 32 लाख रुपए की नकद राशि के गबन के मामले में स्मृति नगर चौकी पुलिस ने



अस्पताल के कैशियर जसविंदर सिंह (46 साल) को गिरफ्तार किया है आरोप है कि वह अस्पताल की राशि बैंक में जमा करने के बजाय अपने पास रखता था। पुलिस ने गबन की रकम से खरीदा गया करीब डेढ़ लाख रुपए कीमत का मोबाइल जब्त किया है स्मृति नगर चौकी प्रभारी अमित आनंद ने बताया कि अस्पताल संचालक मनोज अग्रवाल की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की गई। शिकायत के अनुसार, अनांथा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह करीब छह वर्षों से अस्पताल में कैशियर के पद पर कार्यरत था वह अस्पताल की नकद राशि बैंक में जमा नहीं कर रहा था। पुलिस ने अस्पताल के दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन और बैंक जमा से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया करीब 32 लाख रुपए का गबन सामने आया फजी जानकारी देकर बचता रहा पुलिस जांच में सामने आया कि कैशियर के पद का फायदा उठाकर जसविंदर अस्पताल की रकम अपने कब्जे में रखता था इस के बाद अधिकारियों को ई-मेल के जरिए राशि बैंक में जमा किए जाने की गलत जानकारी भेज देता था। पृष्ठछाछ और उपलब्ध सक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गबन की रकम के इस्तेमाल की जानकारी मिलने पर उसके कब्जे से मोबाइल जब्त किया गया।

मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

भिलाई, 8 सितंबर (तछसं)। प्राणी विजय कुमार रात्रे (28 साल) निवासी देवबलोदा अपनी ड्यूटी से वापस आने के बाद रात्रि करीब 10 बजे उमेश अग्रवाल के साथ बाजार चौक में बैठ था इसी दौरान गांव का देवकुमार ठाकुर वहां आया और प्राणी के गांजा उपलब्ध कराने की मांग की प्राणी ने गांजा नहीं रखने की बात कहने पर आरोपी ने विवाद करते हुए प्राणी के साथ हाथ थपड़ से मारपीट एवं गाली-गलौज की इसके परिणामस्वरूप हथियार लहराते हुए धमकी देने पर प्राणी की नानी लता अग्रवाल, मां सरस्वती रात्रे एवं बहन माया चंदेल बीच-बचाव करने पहुंची इस दौरान आरोपी ने लता अग्रवाल के सिर तथा सरस्वती रात्रे के दाहिने हाथ पर धारदार हथियार से वार कर चोट पहुंचाई और मौके से फरार हो गया रिपोर्ट पर पुरानी भिलाई थाने पुलिस मामले में आरोपी देवकुमार ठाकुर (23 साल) निवासी देवबलोदा को गिरफ्तार किया है ।

सड़क पर स्टंट,पुलिस ने की कार्रवाई

भिलाई, 8 सितंबर (तछसं)। भिलाई जामुल टीआई रakesh खुटेश्वर ने बताया कि थाना जामुल क्षेत्र में बुलेट में तीन युवक सवार होकर तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ स्टैटबाजी करते हुए तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर रील बना रहे थे तथा दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो रही थी पुलिस स्ट्राफ़ द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को रोककर पृष्ठछाछ एवं जांच की गई चालक पवन विवारी निवासी हाउसिंग बोर्ड जामुल जिला दुर्ग को शराब के नशे में वाहन चलाते पाया इस संबंध में थाना जामुल में धारा 281 एवं धारा 184, 185 मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई घटना के लगभग पांच मिनट बाद काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली कार वाहन से कुछ युवक थाना परिसर पहुंचे पुलिस ने उनका अलकोहल परीक्षण कराया गया, जिसमें पांचों युवक शराब के नशे में पाए गए ।

मूल खाताधारकों पर कार्रवाई

भिलाई, 8 सितंबर (तछसं)। भिलाई चार खाता धारकों के खिलाफ पचनाभपुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है बोरसी निवासी अमित प्रसाद के मोबाईल पर अज्ञात का फोन आया था अज्ञात ने जेरोधा शेयर ट्रेडिंग एप में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू करने पर 3-4 लाख रुपए का लाभ खाते में आने का झंझा दिया। एप कैपिटल मोक के बारे में भी अज्ञात ने बताया कि कंपनी द्वारा 25 लाख रुपए लगाकर ट्रेडिंग किया जाता है।

खुले घूमते मवेशियों से अपनी फसल बचाना किसानों के लिए बड़ी चुनौती



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

उत्तई,8 सितंबर। अंचल के किसान इन दिनों भारी जहीजहद और मशकत के बीच अपनी फसल बचाने को मजबूर हैं। आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या और ग्रामीण पशुपालकों की उदासीनता के चलते मवेशी अब घरों में रहने के बजाय सड़कों पर डेरा डाले रहते हैं। फसलों को बचाने के लिए किसानों को अनूठे और संघर्षपूर्ण उपाय अपनाने पड़ रहे हैं।

सुरक्षा के अनोखे जतन

मवेशियों के आतंक से फसलों की रक्षा के लिए किसान पुराने कपड़ों और साड़ियों को खेतों के चारों ओर बांधकर घेराबंदी कर रहे हैं। इसके अलावा, खेल में प्रयुक्त होने वाले नायलॉन के नेट (रस्सी के जाल) का उपयोग करके भी खेतों की किलेबंदी की जा रही है ताकि जानवर अंदर

न घुस सकें।

गौठान व्यवस्था की विफलता और बाहरी मवेशी

ग्रामीण स्तर पर गौठानों में मवेशियों को रखकर उनकी देखभाल के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं पटरी से उतरती नजर आ रही हैं। असामाजिक तत्व लगातार गौठान के सुरक्षा घेरे को तोड़कर मवेशियों को बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ ही, आसपास के गांवों के किसानों द्वारा अपने यहां के आवारा पशुओं को रात के समय गाड़ियों में भरकर अन्य गांवों में छोड़ दिए जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है।

रतजगा और अस्थायी मचान

सेलुट क्षेत्र के किसानों ने फसल सुरक्षा के लिए सामूहिक पहल की है। खार के सभी किसान मिलकर बारी-बारी से रात में

रतजगा करते हैं। इस कार्य के लिए एक मुखिया का चयन किया जाता है, जिसके नेतृत्व में किसान सड़क किनारे अस्थायी झोपड़ी (छपरी) बनाकर पूरी रात जागते हैं और मवेशियों को खेतों से दूर रखते हैं।

शासन-प्रशासन और विकास कार्यों से निराशा

किसानों का कहना है कि सरकारें मंचों पर अन्नदाता का महिमा मंडन तो करती हैं, परंतु मैदानी स्तर पर ऐसी कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस मदद नहीं मिलती, जिससे किसानों में गहरी निराशा है। इसके अलावा, क्षेत्र से गुजरने वाले सिकस लेन सड़कों के जाल ने किसानों के आवागमन और खेतों के पानी की निकासी के पारंपरिक रास्तों को बाधित कर दिया है। मुआजजे की राशि में विसर्गियों और जमीन की नाप-जोख में अंतर को लेकर भी किसानों में भारी रोष और चिंता व्याप्त है।

बीएसपी लोहा चोरी मामले में सियासत और तेज

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई,8 सितंबर। भिलाई स्टील प्लांट से लोहा चोरी के मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने दावा किया कि बीएसपी से हजारों करोड़ रुपए का लोहा चोरी हुआ है और इसके तार सीधे सीएम हाउस से जुड़े हैं बैज ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ छद्म और श्रद्ध से जांच कराने की मांग की है दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान कोयला चोरी से लेकर बस्तर में आयन की चोरी तक के मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि भिलाई स्टील प्लांट से भी हजारों करोड़ रुपए का लोहा चोरी हुआ है बैज ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सरकार में क्या नहीं चल रहा है और क्या चोरी नहीं हो रही है भिलाई स्टील



प्लांट से लोहा चोरी के मामले में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन लगातार आवाज उठा रहे हैं इस के बावजूद सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर दीपक बैज ने सवाल उठाए उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक खुद इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है दीपक बैज ने कहा कि इस मामले की छद्म और श्रद्ध से जांच होने चाहिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं इस

आया था मामला भिलाई स्टील प्लांट से स्कूप चोरी का मामला उस समय सामने आया जब दुर्ग पुलिस ने अकलौरडीह स्थित एक कबाड़ यार्ड में कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में लौह स्कूप बरामद किया था पुलिस के मुताबिक, स्कूप 250 टन लौह स्कूप बरामद हुआ था, जिसकी कीमत करीब 3.22 करोड़ रुपए बताई गई थी जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया बीएसपी के अधिकारी हिमंशु भूषण महिष्कर और ईजीनियरिंग एसोसिएट मनोज देवांगन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया बाद में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 18 तक पहुंचने की जानकारी सामने आई सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप में छद्म के जवाफों पर भी कार्रवाई की गई इस मामले में अब तक 5 से ज्यादा आरोपियों को जमानत मिल चुकी है इन में कर्मि मास्टर्सआईड संजय सिंह भी शामिल है ।

सूर्या मॉल चौक से निगम ने हटाए अवेधे होडिंग-बैनर

भिलाई, 8 सितम्बर। नगर निगम ने शहर के प्रमुख एवं व्यस्ततम सूर्या मॉल चौक पर सड़क किनारे विद्युत एवं अन्य पोत पर लगाए गए अवेधे होडिंग, बैनर एवं पोस्टरों के खिलफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाए जाने से जहां शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही थी, वहीं वाहन चालकों की दृश्यता बाधित होने से सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई थी। निगम के नेहरू नगर क्षेत्र के राजस्व विभाग की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। निगम अमले के पहुंचने की जानकारी मिलते ही संबंधित व्यवसायियों एवं एजेंसियों ने स्वयं पहल करते हुए सड़क किनारे लगे अपने होडिंग, बैनर एवं पोस्टर हटाना शुरू कर दिया।

तीजा मिलन समारोह में उत्साह से शामिल हुई महिलाएं



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

उत्तई, 8 सितंबर। नगर साहू समाज उत्तई के तत्वावधान में माँ कर्मा सामुदायिक भवन शीतला नगर में तीजा मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई । कार्यक्रम का शुरुआत माँ कर्मा माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना और भव्य

कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में समाज की महिलाओं ने बह-चह्दकर हिस्सा लिया।समारोह के दौरान समाज की महिलाओं ने एक से बढ़कर एक मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और समूह नृत्य पेश किए। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने

उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पकवानों पर आधारित व्यजन की बगिया रही, जहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद देखने को मिली।इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेशीला साहू, पायल साहू, सुनीति साहू, नगर पंचायत उत्तई की अध्यक्ष सरस्वती साहू, लक्ष्मी साहू, भुनेश्वरी साहू, विशिष्ट अतिथि विजयलक्ष्मी,एवं राधिका हिरवानी नगर साहू समाज के अध्यक्ष किशोर साहू, सचिव गिरिश साहू, कुशल साहू,भावेश साहू,द्वारिका साहू, खूबी साहू, लक्ष्मण साहू बृज मोहन साहू , शकुंतला साहू,प्रभा साहू,लीलावती साहू, टिकेश्वरी साहू,पुनम हिरवानी, उरालेखा साहू,भुनेश्वरी साहू, तेक्षरी साहू, रामेश्वरी साहू,ऋषि साहू, कृष्णा साहू,यश साहू तथा पंच संचालन शीला साहू सहित हजारों की संख्या में नगर साहू समाज की महिलाएं उपस्थित थी ।

पाटन थाना प्रभारी युवराज साहू ने ग्रहण किया पदभार

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

पाटन,8 सितंबर। यातायात विभाग में पदस्थ रहे युवराज साहू को पाटन थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने सोमवार को पाटन थाने पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद थाना प्रभारी युवराज साहू ने थाने में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, कानून-व्यवस्था, लॉबित प्रकरणों तथा



क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों की जानकारी ली। उन्होंने स्ट्राफ से क्षेत्र को प्रमुख समस्याओं और संवेदनशील स्थानों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त

की। बैठक में थाना प्रभारी ने अपराधों पर प्रभावी निगरान, असामाजिक तत्वों पर निगरानी तथा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा

कि थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिसिंग को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने स्ट्राफ को आम लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने, पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय बनाने तथा क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। नए थाना प्रभारी के पदभार ग्रहण करने के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है।

समाचार संक्षेप

करंट की चपेट में आए नन्हे बंदर ‘वायु’ को बेहतर उपचार के लिए कानन पेंडारी भेजा गया

कवर्धा, 8 सितंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता) । करंट की चपेट में आने से घायल हुए एक नन्हे बंदर के बच्चे ‘वायु’ को बेहतर उपचार एवं आवश्यक देखभाल के लिए कानन पेंडारी वन्य प्राणी चिकित्सालय, बिलासपुर ले जाकर सुरक्षित रूप से चिकित्सालय स्ट्राफ के सुपुर्द किया गया।दिनांक 28 अगस्त 2026 को बंदर के बच्चे के करंट की चपेट में आने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही उसे तत्काल जिला पशु चिकित्सालय, कवर्धा ले जाया गया, जहां डॉ. अभिषेक लोडेंकर एवं उनकी टीम द्वारा प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक चिकित्सकीय

सहयोग प्रदान किया गया।बंदर का बच्चा बहुत छोटा होने के कारण चिकित्सकों की सलाह पर कुछ दिनों तक घर पर ही उसकी नियमित देखभाल की गई। देखभाल के दौरान कुछ सुधार हुआ, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं होने पर उसे पुनः जिला पशु चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार बेहतर उपचार के लिए उसे रायपुर सफारी अथवा कानन पेंडारी, बिलासपुर ले जाने की आवश्यकता बताई गई।इसके बाद वन विभाग कबीरधाम से संपर्क किया गया। इस दौरान एसडीओ श्री अभिनव सर, रेंजर श्री विप्लव जी एवं डिप्टी रेंजर श्री सोनी जी से चर्चा कर आवश्यक सहयोग प्राप्त किया गया। साथ ही वन मंडलाधिकारी महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया गया। वन विभाग के सहयोग एवं आवश्यक प्रक्रिया के बाद आज 07 सितंबर 2026 को घायल बंदर के बच्चे ‘वायु’ को सुरक्षित रूप से कानन पेंडारी वन्य प्राणी चिकित्सालय, बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां उसे आगे के उपचार एवं आवश्यक देखभाल के लिए चिकित्सालय स्ट्राफ के सुपुर्द किया गया। हनुमंत सेवा समिति, कवर्धा के दीपक सोनी ने ‘वायु’ के उपचार एवं सुरक्षित रूप से बेहतर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाने में सहयोग करने के लिए वन विभाग कबीरधाम एवं जिला पशु चिकित्सालय कवर्धा का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से वन मंडलाधिकारी महोदय, वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय, एसडीओ श्री अभिनव सर, रेंजर श्री विप्लव जी, डिप्टी रेंजर श्री सोनी जी एवं पूरी वन विभाग टीम के साथ-साथ डॉ. अभिषेक लोडेंकर एवं जिला पशु चिकित्सालय कवर्धा की पूरी टीम तथा श्री नीलू सोनी जी के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सभी के सहयोग एवं संवेदनशील प्रयासों से नन्हे ‘वायु’ को बेहतर उपचार की उम्मीद मिली है। अब उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है ।

पठनवार प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

पाटन,8 सितंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता) । समग्र शिक्षा, जिला शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मार्गदर्शन में विकासखंड स्तरीय पठनवार प्रतियोगिता का आयोजन डीआरएस, सांगेस (बालक) पाटन में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने स्पीड रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, मैथ मैजिक, स्पीड कैल्कुलेशन एवं क्रिज बैटल सहित विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत पाटन

की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें उचित मंच और अवसर प्रदान करने की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ उनकी सीखने, सोचने और आगे बढ़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं। श्रीमती नायक ने कहा कि पठन-पाठन बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार है। नियमित पठन से समझ, कल्पना शक्ति, भाषा कौशल एवं आत्मविश्वास का विकास होता है। उन्होंने शिक्षकों एवं आयोजन से जुड़े सभी लोगों को सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं अवसर उपलब्ध कराना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में नगर पंचायत पाटन अध्यक्ष योगेश निवकी भाले, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश वर्मा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी डालेन्द्र देवांगन सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न



भिलाई, 8 सितम्बर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता) । स्मृति नगर स्थित छत्तीसगढ़ ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज की प्रांतीय बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राकेश भट्ट ने की। शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा-अर्चना के साथ हुआ। बैठक में दुर्ग जिला अध्यक्ष मन्नु शर्मा के 31 अगस्त को बीएसपी की शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर समाजजनों ने श्रीफल, शील एवं पुष्पहार भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। वीडियो कॉल के माध्यम से ब्रह्म सभ्य पत्रिका के संपादक अक्षय राॅय ने भी मन्नु शर्मा को सेवानिवृत्त पर शुभकामनाएं दीं। समाज के कार्यों को गति देने के लिए सदस्यों से स्वीच्छक सहयोग राशि लेने का निर्णय भी पारित किया गया। वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आय-व्यय का विस्तृत विवरण तैयार कर विधिवत लेखा-परीक्षण कराने पर चर्चा हुई। अंत में समाज के सक्रिय कार्यकर्ता व्यास नारायण शर्मा एवं अयोध्या प्रसाद शर्मा के 3 सितंबर को हुए आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में श्रीमती आभा भट्ट, विष्णु शर्मा, नगर निगम भिलाई के अधिकारी संजय शर्मा, रिसाली के संजय शर्मा, मन्नु शर्मा, संजय ब्रह्मभट्ट, अशोक शर्मा, एस.एन. शर्मा, ए.आर. शर्मा सहित समाज के अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

जामुल नगर पालिका निर्वाचन को आरक्षण प्रक्रिया निर्धारित

जामुल। नगर पालिका परिषद के आगामी निर्वाचन के लिए आरक्षण संबंधी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वाडों का आरक्षण) निगम, 1994 के अधिन नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही 17 सितम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे कलेक्टर सभाकक्ष, दुर्ग में आयोजित की जाएगी।

एक नजर

वृद्धाश्रम संचालन के लिए 15 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

बलौदाबाजार, 8 सितंबर। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। समाज कल्याण विभाग, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामसागर तालाब के पीछे स्थित श्री वाटिका वृद्धाश्रम बलौदाबाजार के आगामी संचालन के 15 सितम्बर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वीच्छिक संस्थाओं, जिन्हें न्यूनतम तीन वर्ष का वृद्धाश्रम संचालन का अनुभव हो, तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकाय कार्यालय उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

बलौदाबाजार, 8 सितंबर। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। सत्र 2027-28 के जवाहर नवोदय विद्यालय लवन के कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2026 हैं। परीक्षा तिथि 10 अप्रैल-2027 (शनिवार) प्रवेश आवेदन संबंधी आवश्यक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन नवोदय विद्यालय सा की वेबसाइट कक्षा-9वीं प्रवेश हेतु https://cbseitms.nic.in/2026/nvsi/ एवं कक्षा-11 वीं प्रवेश हेतु :- https://cbseitms.nic.in/2026/nvs&i 11 पर उपलब्ध हैं।

अतिथ शराब बेचते शराब कोचिया गिरफ्तार, 5.760 लीटर शराब जप्त

बलौदाबाजार 8 सितंबर। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 06.09.2026 को थाना पलारी की पुलिस टीम द्वारा ग्राम भरुवाडीह में घेराबंदी कर अपने उठला में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शराब कोचिया से कुल 73480 कीमत मूल्य का 5.760 बल्क लीटर देशी मसाला/अंग्रेजी गोवा शराब जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना पलारी में धारा 34(2) आबकारी के तहत अपराध क्र. 363/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है।

सात समंदर पार पहुंचा 'साइबर जागृति अभियान', मेलबर्न से मिली सरहना

बलौदाबाजार 8 सितंबर। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। साइबर अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ के पावन संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी 'साइबर जागृति अभियान' (15 अगस्त से 02 अक्टूबर 2026) का प्रभाव अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय की विशेष पहल पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में कार्यरत भारतीय मूल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री विवेक यदु ने इस अभियान से जुड़कर छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रयासों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और आम नागरिकों से इस अभियान का लाभ लेने की अपील की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री विवेक यदु ने मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) से साझा किए अपने विचार:- ?तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले श्री विवेक यदु ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से अपना विस्तृत वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि, -एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते मैं तकनीकी बारीकियों और साइबर अपराध की गंभीरता को गहराई से समझता हूँ। आज साइबर अपराध दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आम लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं।

जिले मे 17 सितंबर से शुरू होगा 'सेवा संकल्प अभियान',घर-घर जलेंगे आशीर्वाद के दीये

- 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा एक माह का विशेष अभियान
- जनसहभागिता से आयोजित होंगे 12 प्रमुख कार्यक्रम, कलेक्टर ने ती समीक्षा बैठक
- तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार 8 सितंबर। जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करने, 'विकसित भारत 2047' का सामूहिक संकल्प लेने और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बलौदाबाजार जिले में 17 सितंबर से एक माह का 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू होने जा रहा है। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी रहेगी। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सोमवार को अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर अभियान की तैयारियों के संबंध में

किसानों की खुशहाली और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर,8 सितंबर। रायपुर सांसद एवं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने किसानों की आर्थिक सुस्थि, कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा आम नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इन योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाओं को निरंतर और सुदृढ़ करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सांसद अग्रवाल ने कहा कि भारत की कृषि व्यवस्था को अधिक समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं आधुनिक बनाने के लिए किसानों को समय पर उर्वरक (खाद) की उपलब्धता, नई तकनीकों का विस्तार तथा सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी कृषि प्रधान क्षेत्रों में इन प्रयासों का लाभ किसानों और ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे, इस दिशा में निरंतर कार्य किया जाना चाहिए। सोमवार को रसायन उर्वरक सम्बन्धी संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के बाद सांसद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को किफायती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा व्यापक व्यय कृषि क्षेत्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उर्वरक विभाग के अनुसार पिछले पांच वर्षों में यूरिया सब्सिडी योजना पर लगभग 8.16 लाख करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

सांसद अग्रवाल के अनुसार इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, तकनीक आधारित निगरानी तथा उर्वरक के वास्तविक उपयोग की जानकारी

को और सुदृढ़ करना आवश्यक है। कृषि उपयोग के लिए निर्धारित सब्सिडी वाले यूरिया का लाभ किसानों तक ही पहुंचे, इसके लिए संभावित औद्योगिक डायवर्जन की रोकथाम तथा औद्योगिक उपयोग के बेहतर सत्यापन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप यूरिया के आवंटन, आपूर्ति और उपलब्धता की निरंतर समीक्षा से किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि उर्वरक क्षेत्र में दीर्घकालीन सुधारों के साथ नैनो उर्वरक और नमो ड्रोन दीदी जैसी पहले भारतीय कृषि को आधुनिक एवं अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों की वास्तविक सफलता किसानों की

लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आय के अवसरों से सुनिश्चित होगी। इसके लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और आवश्यक सेवा व्यवस्था को निरंतर मजबूत किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कृषि की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए आधुनिक कृषि तकनीकों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने में सहायक होगा।

सांसद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को आम नागरिकों के स्वास्थ्य व्यय में राहत पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाओं की किफायती उपलब्धता से विशेष रूप से गरिब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को लाभ मिल रहा है। 31 जुलाई 2026 तक देश में 20,547 जन औषधि केंद्र स्थापित हो चुके हैं, जिनमें 10,457 ग्रामीण

क्षेत्रों में हैं। जिनमें छत्तीसगढ़ में 355 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत दवाएं प्रमुख ब्रांडेड उत्पादों की तुलना में सामान्यतः 50 से 80 प्रतिशत सस्ती हैं तथा नागरिकों को 745,000 करोड़ से अधिक की अनुमानित संचयी बचत हुई है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि जन औषधि के विस्तार के साथ गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के प्रति चिकित्सकों एवं मरीजों का विश्वास बढ़ाना भी आवश्यक है। जागरूकता, गुणवत्ता संबंधी जानकारी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय से इस योजना का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों की उपलब्धता और दवाओं की नियमित आपूर्ति को सुदृढ़ कर गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को और अधिक राहत पहुंचाई जा सकती है।

यादव समाज रायपुर की विशाल बाइक रैली ने दिया सामाजिक एकता का संदेश

रायपुर 8 सितंबर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर यादव समाज रायपुर के तत्वावधान में 05 सितंबर 2026 को राजधानी रायपुर में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ महोदयवाट स्थित राधा-कृष्ण मंदिर से हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए काली मंदिर, शहीद कौशल यादव चौक पहुंची, जहां भव्य सभा का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में यादव समाज के विभिन्न वर्गों, संगठनों एवं क्षेत्रों से आए सामाजिक प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, महिलाओं, युवाओं तथा समाज के प्रबुद्धजनों ने



अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी मित्र मंडल समिति, श्री प्रभाकरकांत यादव, सचिव, श्रीमती ममता यादव, सदस्य; श्रीमती वेदकुमारी यादव, सदस्य छत्तीसगढ़ यादव राधा-कृष्ण के स्वरूप में रथ पर सुशोभित रहें। उनके साथ सहयोगियों की उपस्थिति ने रैली को विशेष आकर्षण प्रदान किया।

सभा में मुख्य अतिथि के रूप में श्री देवनारायण यादव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सरगुजा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्रीमती निर्मला यादव, अध्यक्ष नगर पंचायत विश्रामपुर; श्री महेश यादव, अध्यक्ष नगर पंचायत राजिम; श्री रिखी राम यादव, अध्यक्ष नगर पंचायत गरियाबंद; श्री सुधीर यादव, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ यादव समाज; श्रीमती ललिता यादव, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग टेक्नार यादव समाज; श्री जितेंद्र बहादुर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष; श्री निरंजन यादव; श्री कमल यादव; सुश्री शोभा यादव; श्रीमती अरुणा यादव, श्रीमती भारती यादव, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग प्रयासम प्रातिशील यादव समाज; श्रीमती लक्ष्मी यादव, सदस्य प्रातिशील यादव महसभा; श्री जय यादव, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ यादव एकता कल्याण संगठन एवं टीम; श्री माधव यादव,

को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना होगा। श्री यादव ने कहा कि समाज के विकास के लिए सभी वर्गों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर एक होकर कार्य करने की आवश्यकता है। जब समाज संगठित होगा, एक-दूसरे के सुख-दुःख में सहभागी बनेगा और सामूहिक रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा, तभी समाज का वास्तविक एवं सर्वांगीण विकास संभव होगा।

उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित यह विशाल बाइक रैली केवल उत्सव का माध्यम नहीं, बल्कि यादव समाज की एकता, संगठन और सामाजिक समरसता का मजबूत संदेश है। उन्होंने इस पहल के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए समाज के सभी वर्गों से इसी भावना के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यादव समाज विभिन्न वर्गों और संगठनों में विभाजित है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी वर्ग आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर सामाजिक एकता और भाईचारे के साथ एक मंच पर आएँ। इसी उद्देश्य से राजधानी रायपुर से इस विशाल बाइक रैली के माध्यम से पूरे समाज को हम सब एक हैं का संदेश दिया गया। श्री

राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का शुभारम्भ

बलौदाबाजार,8 सितंबर। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। जिले में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता 2026-27 का शुभारम्भ 8 सितम्बर 2026 को अपराह्न 3 बजे होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य एवं राज्यस्व मंत्री टंकुराम वर्मा की अध्यक्षता में डेयर स्टेडियम हॉल, कॉलेज रोड कसडोल में स्पर्धा का उद्घाटन समारोह आयोजित है। इस अवसर पर जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित,सांसद,विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 8 से 11 सितम्बर तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रग्बी, गतका एवं फैसिंग विधा में रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर,जगदलपुर एवं सरगुजा संभाग के 520 खिलाड़ी भाग लेंगे जिसमे 260 -260 बालक एवं बालिका शामिल हैंइसके साथ ही लगभग 100 कोच एवं टीम मैनेजर सभी संभाग के शामिल होंगे। रग्बी खेल प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका 19 वर्ष आयु वर्ग, गतका मे 17 से 19 वर्ष बालक -बालिका,फैसिंग मे 17 से 19 वर्ष आयु के बालक -बालिका शामिल होंगे। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। खिलाड़ी एवं कोच के ठहने एवं भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

फर्जी प्रमाणपत्र से नियुक्ति के मामले में जिला प्रशासन ने सहायक शिक्षक को किया निर्लंबित

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार,8 सितंबर। जिला प्रशासन ने फर्जी व कुटर्चित दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने वाले एक सहायक शिक्षक पर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कसडोल विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला कौजया में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) रामेश्वर प्रसाद साहू को तत्काल प्रभाव से निर्लंबित कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार पिसीद (कसडोल) निवासी हेमदास मानिकपुरी ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि रामेश्वर प्रसाद साहू ने वर्ष 2011 में फर्जी डी.एड. अकसूची (सत्र 2008, सत्र नंबर 47240442) प्रस्तुत कर शिक्षकमी वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। संदेह तब गहराया जब नियुक्ति के 11 साल बाद उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर से दोबारा डी.एड. किया। इससे

स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2011 की नियुक्ति के समय जमा किया गया प्रमाण पत्र पूरी तरह फर्जी और कुटर्चित था। जांच में खुली पोल- कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जनपद पंचायत कसडोल और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कसडोल द्वारा जांच की गई।

जांच रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ी पाई गई। शिक्षक द्वारा 4 जनवरी 2011 को कार्यभार ग्रहण करते समय सलन डी.एड. प्रमाण पत्र के सील पर 'जिला बलौदाबाजार' अंकित था, जबकि बलौदाबाजार जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ था। एक अन्य प्रतिवेदन के सील में 'जिला रायपुर' दर्ज था। जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत पाया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत शिक्षक रामेश्वर प्रसाद साहू को तत्काल प्रभाव से निर्लंबित कर दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री टंकुराम वर्मा ने 150 सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का किया सम्मान



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 8 सितंबर। स्व. सोनचंद स्मृति फ़उंडेशन के तत्वाधान में नगर भवन, बलौदाबाजार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कैबिनेट मंत्री टंकुराम वर्मा ने 150 सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान कर उनके शिक्षा एवं अपेक्षित मजबूती नहीं मिल सकी। उन्होंने इस विचार को केवल भाषण तक सीमित न रखते हुए अपने परिवार से इसकी शुरुआत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं कोसरिया यादव समाज से होने के बावजूद अपने परिवार के सदस्य का विवाह छेरिया यादव समाज में करने का निर्णय ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता की शुरुआत दूसरों से नहीं, बल्कि अपने घर और परिवार से होनी चाहिए। इसी भावना के साथ उन्होंने आने वाले समय में इस विवाह समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया है।

श्री विनोद यादव का यह निर्णय कार्यक्रम में उपस्थित समाजजनों के बीच चर्चा का विषय बना और इसे सामाजिक समरसता एवं एकता की दिशा में एक सकारात्मक एवं अनुकरणीय पहल के रूप में देखा गया। कार्यक्रम में यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया कि समाज की शक्ति उसकी संख्या में नहीं, बल्कि उसकी एकजुटता, संगठन, आपसी सहयोग और सामाजिक समरसता में है।

उन्होंने सभी गुरुजनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन से समाज की नई पीढ़ी को दिशा देते हैं। आज जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान किया जा रहा है, उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बच्चों को शिक्षित करने और राष्ट्र निर्माण में समर्पित किए हैं। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा डॉ. सनम जांगड़े, जनपद अध्यक्ष सुलोचन यादव, टेसू लाल धूरंधर, स्व. सोनचंद स्मृति फ़उंडेशन के अध्यक्ष पुष्पराज वर्मा सहित पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग क्विज में पंजीकरण 30 सितंबर तक

■ प्रधानमंत्री से भेंट और सीधे संवाद का मिलेगा अवसर

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार,8 सितंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2027 के अवसर पर होने वाले विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के पहले चरण की ऑनलाइन प्रसोचनी प्रतियोगिता में पंजीयन 30 सितंबर 2026 तक करा सकते हैं। इस प्रतियोगिता में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को अंतिम चरण में प्रधानमंत्री से भेंट और संवाद का अवसर मिलेगा। इसमें शामिल होने के लिए युवाओं को मांय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। ऑनलाइन आयोजन होने से देशभर के युवा आसानी से शामिल हो सकते हैं। युवाओं को अपनी जानकारी, विचार और नेतृत्व कौशल प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रतियोगिता देती है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के अंतिम चरण में

पहुंचने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री से भेंट और सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। युवाओं के लिए यह अनुभव नेतृत्व क्षमता को निखारने और भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चरण बढ़ा प्रक्रिया-पहले चरण में देश भर में ऑनलाइन क्रिज प्रतियोगिता होगा जिसमें प्रतिभागी ऑनलाइन भाग लेंगे।प्रथम चरण में सफल प्रतिभागी द्वितीय चरण ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेंगे।तीसरा चरण व्यक्ति होगा जिसमें द्वितीय चरण में सफल 50 प्रतिभागी जिला स्तर पर भाग लेंगे। अंतिम चरण में तीसरे चरण में सफल प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तर के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होगा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने इस प्रतियोगिता में अधिक अधिक सहभागिता हेतु जिले के युवाओं को समय पर पंजीयन कराने का आह्वान किया है।इसके साथ ही खेल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के अंतिम चरण में निर्देश दिये हैं।

कार्यक्रम में मारपीट कर मोबाइल-नकदी छीनने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार 8 सितंबर। पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय के कुशल निर्देशन में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा गुंडागर्दी, मारपीट व लूटपाट जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त व प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस चौकी गिरौदपुरी द्वारा ग्राम बरेली में कार्यक्रम के दौरान मारपीट व छीना-झपटी करने वाले 04 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। दिनांक 06.09.2026 को प्रार्थी तरुण कुमार पटेल (उम्र 16 वर्ष, निवासी कौवाताल) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 04.09.2026 को शाम वह अपने साथियों के साथ ग्राम बरेली में एक कार्यक्रम देखने गया था। इसी दौरान ग्राम बरेली के आरोपी अधिषेक साहू, नागेश साहू व उनके अन्य साथियों द्वारा अश्लील गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्का, लात एवं हाथ में पहन कड़े (चुड़ा) से प्रार्थी व साथियों के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट के दौरान आरोपियों ने प्रार्थी के गिर जाने पर उसकी जेब में रखा रियलमी मोबाइल (सिम सहित) एवं नगदी 21,500/- जबरन झपटकर निकाल लिए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी गिरौदपुरी (थाना गिधौरी) में अपराध क्र. 177/2026, धारा 296, 115(2),304(2),3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस की त्वरित कार्यवाही एवं गिरफ्तारी-मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी गिरौदपुरी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी व आहतों के कथन दर्ज किए गए। त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने दबिश देकर नामजद 04 आरोपियों को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपराध कािर्त करना स्वीकार किया गया, जिस पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया।

दो पक्ष न्याय के लिए अदालत जाते हैं। दोनों को उम्मीद रहती है कि उनके साथ अदालत न्याय करेगी। दोनों पक्ष को यह उम्मीद रहती है कि तब ही दो तीनों जाते हैं अदालत के सामने जो बयान होते हैं, जो सबूत रखे जाते हैं अदालत का काम उन सबूतों के आधार पर न्याय करना होता है अदालत गवाहों के बयान व जांच एजेंसी के पेश किए सबूतों के आधार पर फैसला करती है, न्याय करती है। स्वाभाविक है कि दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष में फैसला होता है, एक पक्ष के साथ न्याय होता है एक पक्ष को लगता है कि उसके साथ न्याय हुआ है और एक पक्ष को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ कुछ लोग कहते हैं कि यह अधूरा न्याय है लेकिन सच तो यह है कि कोई भी न्याय सिर्फ न्यायाधीश के द्वारा ही हो सकता है, न्याय ही न्याय है, न्याय ही न्याय होता है, वह अधूरा या पूरा नहीं होता है। अदालत अगर अधूरा न्यायाधीश करती होती तो लोग अदालत के पास न्याय के लिए क्यों जाते। अदालत तय प्रक्रिया के हिसाब से न्याय करती है, इसलिए लोग न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा करते न्याय के लिए अदालत जाते हैं क्षीरम कांड में अदालत ने न्याय किया है, यह सिर्फ न्याय है इसे न्याय ही हमसजा जाना चाहिए। २५ मई २०१३ को कांसिस की परिवर्तन यात्रा के दौरान श्रीमती मंजी में एडवोकेट नक्सली हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित २९ लोग मारे गए थे। इष्टना के बाद एनआईए ने मामले की जांच शुरू की एनआईए इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पाई इन्हें के खिलाफ एक आईएन सी में सितंबर २०१४ से मुकदमा चल रहा था एनआईए ने २८ सितंबर

राशिफल

अजक का दिन ई उम्मीर और राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आधिकार परा होने से मन हल्ला और खुश महसूस करेगा। जीवनशष्ठी के साथ चल रही दूरियां बातचीत और समझदारी के सम हंगी और रिश्ते में फिर से मिठास लोटेगी।

अज कुच प्रभावशाली और खास लोगों से मुलाकात आपके करियर या कारोबार के लिए नए अवसर ला सकती है। हालांकि, दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। संतान की नौकरी में तरक्की से परिवार में गर्व और खुशी का माहौल बनेगा।

अज आपकी सुखबुझ और रहती समय पर फसल लेने की क्षमता आपकी दूसरी से आगे रहेगी। वित्तीयों की बातों में आकर कोई जल्दबाजी वाला कदम न उठाए। संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकता है। नौकरी में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए जूनियर का सहयोग भी काफी उपयुगी रहेगा।

अज वैवाहिक जीवन में प्यार, समझ और आपसी सहयोग का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलेगा। माताजी से किया हुआ कोई वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को संतोह आए। नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का विचार बन सकता है। लेकिन अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। कारोबार में, आपने नए विचार नई ऊंचाइयों का रास्ता खोल सकते हैं।

अज खुशियां और उल्लसियां आपका इंतजार कर रही हैं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में अपमान और फजबूती बढ़ाएगा। लंबे समय अटका हुआ बिजनेस डील आधिकारका मजबूत होने की उम्मीद है।

अज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका अच्छा सदा दे सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं और आय में बढ़ोतरी से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनशष्ठी के लिए कोई खास चीज खरीदना रिश्ते में प्यार और अपमान बढ़ाएगा। हालांकि निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें और पूरी जानकारी के बाद ही कदम उठाएं।

अज दिन काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रह सकता है। कोशिश करें कि जरूरी काम खुद सभालें और हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। किसी पार्टी या समारोह में जाने का मौका मिल सकता है, जहां आपकी बातचीत और व्यक्तिगत लोगों को प्रभावित करेगी।

अज सहेत में थोड़ा उत्तर-बढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए खान-पान और आराम पर विशेष ध्यान दें। अचानक किसी यात्रा की योजना बन सकती है। कारोबार के कोई पुरानी समस्या भाई-बहनो के सहयोग से सुलझने की उम्मीद है। विद्यार्थियों के भीतर कुछ नया सीखने और अलग करने की इच्छा जागगी, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती है।

अज मन की कोई इच्छा पूरी न होने से थोड़ी बेचैनी या निराशा महसूस हो सकती है। काम में भी मन कलगे तो खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना बेहतर होगा। परिवार में किसी सदस्य को सहेत को लेकर भागदौड़ करने पड़ सकती है।

अज अचानक बन वाला मिलने के योग बन सके हैं। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इराना अटका इड़ा पैसा भी वापस मिल सकता है। नौकरी को तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी खबर का इंतजार खूब हो सकता है। घर में नए मेहमान के आने से खुशियों की रोक बढेगी।

अज का दिन सामान्य से बेहतर और कुछ नई संभावनाओं वाला रह सकता है। अचानक यात्रा के योग्य बन सकते हैं। संतान ने किसी पढ़ाई में हिस्सा लिया था तो उसका परिणाम अच्छे लिए खुशी लेकर आ सकता है। नई नौकरी के लिए किया गया प्रयास भी सफल होने की उम्मीद है। विद्यार्थियों के लिए उत्तु शिक्का के नए रास्ते खुल सकते हैं और भविष्य को लेकर उत्साह बढ़ेगा।

अज आकाश में उड़ते-चढ़ाते के कारण मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें और किसी भी दस्तावेज या समझौते को बिना पढ़े स्वीकार न करें। दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचें। पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मन को स्थिति मिलेगी।

न्याय न्याय होता है, पूरा

२०२० को सप्टीमेंट्री चार्जशीट पेश की जिसमें गिरफ्तार नक्सलियों के बयानों के आधार पर ३० और नक्सलियों को भी आरोपी बनाया गया १३ साल, २८४ सुनवाई और १०१ गवाही को सुनने के बाद अदालत ने पांच सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए १० लोगों को दोषी ठहराया गया है। मामले में नामजद कई आरोपी फरार हैं। अदालत को इस मामले में सबूतों के आधार पर न्याय करना था। उसने कर दिया है। अदालत ने अपना काम कर दिया है। अब सवाल उठाने वाले सवाल उठाने रहेंगे। कोई कहे हम सतुत नहीं हैं, कोई कहे कि यह पूरा न्याय नहीं है। कि कोई कहे कि असली गुनहारों को बचा लिया गया है। कोई कहे कि असली गुनहारों को तो सजा नहीं मिली है। कहे हैं से कुछ नहीं होता है, कहे हैं वालों को सामने १३ साल का समय था वह जो कह रहे हैं, उसके सबूतों पर एजेंसी को देने थे, १३ साल तक जांच में सतुत किसी ने मुहिया नहीं करायी और न्याय नहीं हुआ कह रहे हैं तो उनके सामने फिर मौका आया जब मामला ऊँची अदालत में जाएगा। वह ऊँची अदालत में सतुत पेश कर सकते हैं और दोषी लोगों को सजा दिला सकते हैं। कहें पार कानूनी तौर पर किसी मामले का फैसला निचली अदालत में हो जाता है तो लेकिन राजनीतिक रूप से मामले का भी समाप्त नहीं होता है।

या अधूरा नहीं होता है.....

क्योंकि दोनों पक्ष मामले में राजनीति करना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि जो मामला अदालत में खत्म हो गया है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर वह मामले को खत्म मान लेंगे तो राजनीति कैसे करे, एक दूसरे को घटना के लिए दोषी कैसे बताएं। १३ साल से झीरम कांड एक दूसरे पर आरोप लगाने का मुद्दा रहा है। एक दूसरे पर झीरम कांड के लिए दोष मढ़ते रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद भी कांग्रेस व भाजपा नेताओं के आप बयान से साफ है कि यह मुद्दा दोनों के बीच आरोप लगाने का मुद्दा बना रहेगा। २९ लोगों की हत्या के लिए वह एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। एक दूसरे से सवाल पूछते रहेंगे। यह सिलसिला अगर १३ साल से चल रहा है तो अदालत को फैसला आने के १३ साल बाद चलता रहेगा। झीरम कांड राज्य में राजनीति का स्थायी मुद्दा रहा है और स्थायी मुद्दा अगले १३ साल तक बना रहेगा। यह तो सच है कि नक्सलियों ने झीरम घाटी में हत्या की है। सब जानते हैं कि नक्सली किसी नेता या किसी ग्रामीण क्यों करते रहे हैं। उनका हत्या का मकसद तो हमेशा से ही क्षेत्र विशेष में अंतक फैलाना रहा है। हर हत्या का उनका एक ही मकसद था कि लोगों में भय पैदा करना ताकि उन क्षेत्र में लोग डर कर न आएँ, जो रहते हैं वध डरकर रहें। नक्सलियों ने

विदेश

जर्मनी में कट्टरपंथी एएफडी की छोटी जीत के बड़े मायने



संजय सक्सेना, लखनऊ,

आजकल जर्मनी में अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड (एएफडी) की एक छोटी-सी जीत की बड़ी चर्चा हो रही है। एएफडी की छोटी-सी जीत से पूरे यूरोप और खासकर इस्लामी जगत में बेचनी नज़र आ रही है। यह जर्मनी की एक ऐसी धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन में जर्मन वर्गों में

पूछा लाल दा दिया है। 2013 में स्थापित हुई इस पार्टी ने प्रवासियों के विरोध, यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रति अविश्वास और जर्मन राष्ट्रवाद के दम पर देश के चुनावी परिदृश्य को बदलकर लक्ष्य दिया है। अल्टरनेटिव फॉर डॉयलैण्ड की स्थापना 6 फरवरी 2013 को हुई थी। शुरुआत में, इस पार्टी का गठन अर्थशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया था, जो मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र के आर्थिक सहायता पैकेज के खिलाफ थे। हालांकि, 2015 के यूरोपीय शरणार्थी संकट के दौरान पार्टी का रुख पूरी तरह से एक बड़ा बदलाव आया। पार्टी ने अपने प्रमुख उद्देश्यों में शरणार्थी और प्रवासियों के आने पर पूर्ण विरोध लगाना है। पार्टी अवैध शरणार्थियों को तेजी से निर्वासित करने की वकालत करती है। उनका मानना ​​है कि प्रवासियों के आने से जर्मनी की पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। वे स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज जलाने और राष्ट्रगान गाने जैसी नीतियों को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही पार्टी खुले तौर पर जर्मनी में बढ़ते इस्लामीकरण और बहुसंस्कृतिवाद का विरोध करती है। जर्मनी की खुफिया एजेंसी की रिपोर्टों के अनुसार, इसके नेताओं द्वारा कई बार जनविरोधी और नस्लवादी बयान दिए गए हैं। पार्टी यूरोपीय संघ की मौजूदा व्यवस्था में बड़ बदलाव या उससे पूरी तरह बाहर निकलने की बात भी करती है। धार्मिक रुख की बात करते तो आधिकारिक तौर पर एक ही स्वयं को ईसाई-यहूदी संस्कृति और पारिवारिक संरचनाओं, जैसे एक पुरुष और एक महिला का विवाह, और रूढ़िवादी ईसाई सामाजिक मूल्यों का पुरजोर समर्थन करती है। वे प्रगतिशील या एंथ्रोपिक उदारवादी विचारों, जैसे स्कूलों में इंद्रधनुस झंडे डगाना, का विरोध करते हैं। इसके विचार, पार्टी का रुख इस्लाम

के प्रति बेहद सख्त है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस्लाम जर्मनी का हिस्सा नहीं है और वे मस्जिदों के मीनारों तथा अजान के सार्वजनिक लाउडस्पीकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते रहे हैं। हालांकि पार्टी ईसाई धर्म की रक्षक बनती है, लेकिन जर्मनी के मुख्यधारा के चर्च, जिनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों शामिल हैं, अवसर एएफडी की नस्लवादी और विभाजनकारी नीतियों का सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं। इसके बावजूद, देश के पारंपरिक ईसाई और रूढ़िवादी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इस पार्टी की तरफ़ आकर्षित हुआ है जर्मनी की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के सह-नेतृत्व एएफडी में कोई एक अकेला सर्वोच्च नेता नहीं है। यह पार्टी सच-नेतृत्व के मॉडल पर चलती है। वर्तमान में एलिस विडेल पार्टी



की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली चेहरा हैं। वे संसद में पार्टी की संसदीय समूह की नेता और राष्ट्रीय सह-अध्यक्ष हैं। एक पूर्ण निवेश बैंकर होने के नाते, वे पार्टी को एक आधुनिक और आर्थिक रूप से सक्षम छवि देने का प्रयास करती हैं। उनके साथ टिनो कूपल्ला पार्टी के राष्ट्रीय सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। कूपल्ला मुख्य रूप से पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और पूर्वी जर्मनी के कामकाजी वर्ग के बीच समन्वृत पकड़ रखते हैं। प्रांतिय स्तर पर उत्तरिच संगीमंड का नाम बेहद तेजी से उभरा है, जिन्होंने सैक्सनी-अनहाल्ट के चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करते हुए ऐतिहासिक जीता दर्ज की है। इन दोनों के अलावा ब्योन होके थूरिंगिया राज्य में एफएडी के नेता हैं। इन्हें पार्टी के भीतर सबसे करिश्मियरस्थ और विवादात्त धड़े का जनक माना जाता है, और जर्मन खुफिया एजेंसियां इन्हें आधिकारिक तौर पर एक दक्षिणपंथी चरमपंथी मानती हैं। जर्मनी के संसदाय में 16 राज्य हैं, और एफएडी की विस्तारवादी नीति दर्शक के भीतर बेहद आक्रामक रही है। भूतपूर्व पूर्वी जर्मनी के राज्यों जैसे सैक्सनी-अनहाल्ट, थूरिंगिया,

नव दशकों में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या आंतक फैलाने के लिए की है। इनकी हत्या का मकसद किसी राजनीतिक नहीं रहा है। वह किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए हत्या करते हैं नहीं थे, वह तो राजनीतिक नेताओं की हत्या भी आंतक फैलाने के लिए करते थे कि वह उनसे आम लोगों सहित शासन को संदेश देते थे हत्या करके कि हमारे अगले में हम किसी को भी मार सकते हैं। यहां हमका जेठ है, हम जो चाहेंगे वही होगा इसलिए कांग्रेस नेताओं का एक मकसद भी आंतक फैलाना रहा हो। हर मामले में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष न्याय से संतुष्ट हो तो दूसरा पक्ष न्याय से असंतुष्ट हो सकता है। हमारे यहां व्यवस्था है कि अगर किसी की लगता कि एक अदालत ने उसके साथ न्याय नहीं किया है तो उसके लिए न्याय के लिए ऊपर की अदालत है, वह ऊपर की अदालत में न्याय के लिए जा सकते हैं। क्षीरम मामले में हाईकोर्ट जाने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि वहां भी कोई फैसला होगा तो सबूत के आधार पर होगा। वहां भी न्याय मांगने वालों को सबूत तो देना ही होगा। बाहर राजनीति के लिए तो कोई आरोप किसी पर लाया जा सकता है लेकिन अदालत में कोई फैसला किसी के आरोप से तो होता नहीं है। अदालत पेश किए गए सबूत के आधार पर फैसला करती है। चाहे वह निचली अदालत हो या ऊपरी अदालत। निचली अदालत हो या ऊपरी अदालत जैसा सबूत पेश किया जाएगा वैसा फैसला किया जाएगा।

पक्सनी और ब्रॉडेनबर्ग में एफएफडी इस समय सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है। सैक्सनी-अनहाल् के हालिया चुनावों में पार्टी ने करीब 44 प्रतिशत वोट हासिल कर मुख्यधारा की सभी पार्टियों को पछाड़ दिया है। शुरुआत में पश्चिम राज्यों के अमीर और उदारवादी मतदाता इस पार्टी से दूर थे, लेकिन हालिया औद्योगिक मंदी, उर्जा संकट और बढ़ती महंगाई के कारण पार्टी ने पश्चिमी जर्मनी के राज्यों में भी अपनी ठेठ मजबूती की है। वर्तमान में, जर्मनी के 16 में से 15 राज्यों की विधानसभाओं में पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। जर्मनी की राष्ट्रीय संसद में यह मुख्य विपक्षी दलों में से एक है। इसके अलावा, यूरोपीय संसद के चुनावों में भी यह जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिससे साबित होता है कि इसका प्रभाव केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड यानि एफएफडी आज जर्मनी की राजनीति में उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जहां इसके समर्थक इस देश की संस्कृति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बचाने वाला एकमात्र विकल्प मानते हैं, वहीं जर्मनी के मुख्यधारा की पार्टियाँ और खुफिया एजेंसियाँ इसे देश के लोकतांत्रिक ढाँचे और सामाजिक ताने-बाने के लिए एक गंभीर खतरा मानती हैं। जर्मनी की राजनीति में इस पार्टी का उभार आने वाले समय में पूरे यूरोप की दिशा तय करेगा। जर्मनी को हमेशा से यूरोपीय संस

को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली धुरी माना गया है। यदि जमीनी को भीतर एण्फडी जैसी सूर्य-संदेहवादी पार्टी सत्ता में या उसके करीब आती है, तो बर्लिन की घेरले राजनीति की पूरी तरह बिखर जाएगी। इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ के केंद्रीय मुख्यालय (ब्रसेल्स) में सामूहिक निर्णय लेना बेहद कठिन हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन की नीतियों (हरित समझौते) और वित्तीय सुधारों पर सहमति बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, जिससे पूरा यूरोपीय संघ नीतिगत रूप से पंगु हो सकता है इसके अलावा यूरोप के अन्य देश, जो वर्तमान में प्रवासियों की समस्या से जुझ रहे हैं, अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील करने पर मजबूर हो जाएंगे। एण्फडी की कट्टर आब्रजन विरोधी नीतियों को दरवाजे हट पड़ोसी देश (जैसे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस और डेनमार्क) भी अपनी आंतरिक सुरक्षा को कड़ा करेंगे। इसके यूरोपीय संघ के भीतर बिना वीजा या पासपोर्ट के स्वतंत्र रूप से आने-जाने की जो 'शेंगेन व्यवस्था' है, वह खतरे में पड़ जाएगी और देशों के बीच आपसी मतभेद और सीमा विवाद बढ़ेंगे।

सत्य निकेतन हादसा: जिम्मेदार अधिकारियों पर हो ठोस कार्रवाई

हादसा

ललित गर्ग

दिल्ली के सत्य चिकित्तन में रविवार को पांच मंजिला छात्र-पीजी भवन का भरभराकर गिरावला केवल एक दर्दनाक हादसा नहीं है। उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जो भवन बनने देती है, उसमें अनधिकृत निर्माण होने देती है, उसमें विद्याधियों को रहने देती है, उसकी सुरक्षा कमजोरियों को वर्षों तक नजरअंदाज करती है और फिर उसके ढह जाने के बाद जागती है। इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की सूचना है और कई लोग घायल हुए हैं। प्रांरिक पिपेटों के अनुसार भवन में बेसमेंट और कई ऊपरी मंजिलों में मरमत्त या निर्माण संबंधी काम चल रहा था। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच और भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हादसे के बाद किसके खिलाफ एफआईआर होगी? असली सवाल यह है कि हादसे से पहले जिम्मेदार अधिकारी कहाँ थे? यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन था, यदि भवन का स्वीकृत नक्शा नहीं था, यदि अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं, यदि बेसमेंट में निर्माण चल रहा था, यदि भवन छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और यदि यह संरचनात्मक रूप से जोखिमपूर्ण था, तो इन सबका तात् प्रशासन को जब क्यों नहीं चला जब जब निर्माण हो रहा था?

सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के आसपास विद्यार्थियों का प्रमुख केंद्र है। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों युवा यहां अपने भविष्य के सपने लेकर आते हैं। वे छोटे-छोटे कमरों, पीजी और किराये के मकानों में रहकर पढ़ते हैं। उनके माता-पिता अपनी जीविकोपार्जन की कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि राजधानी में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन गरीब शिक्षा की तलाश में निकला युवा एक ऐसी इमारत में पहुंचता है, जिसकी नींव ही नियमों और सुरक्षा के साथ समझौते पर टिकी हो, तो विकास की हमारी पूरी अवधारणा कटघरे में खड़ी हो जाती है और यह कोई पहली चेतावनी नहीं है। 2022 में भी सत्य निकेतन में निर्माणधीन चार मंजिला इमारत ढहने से दो मजदूरों की मौत हुई थी और चार लोग घायल हुए थे। उस समय भी निर्माण कार्य, सुरक्षा और भवन की निगरानी में सवाल उठे थे। लगभग चार साल बाद उसी स्थल है कि फिर एक बड़ी इमारत ढह गई। इसका अर्थ है कि हमने घटना से सबक लेने के बजाय घटना को एक समाचार की तरह देखा और आगे

बढ़ गए।

यहाँ भ्रष्टाचार की बात करते समय एक सावधानी भी जरूरी है। किसी अधिकारी या व्यवसायी को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं। लेकिन यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि निजमों के विरुद्ध निर्माण को जानबूझकर नुकसान अंदाज किया गया, निरीक्षण में लापरवाही हुई या किसी प्रकार की मिलीभगत रही, तो जिम्मेदारों केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रहने चाहिए। जिसने निजम तोड़े और जिसने निलय तोड़ने दिए-दोनों को जवाबदेह बनाना होगा। सत्य



नितेकन की भासदी की जुलाई 2024 के पुराने
सकल नगर हादसे से अलग करके नहीं देखा जा
रजता। वहां राव आइएस स्टडी सिविल के
बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा
अभ्यर्थियों-तनीया सोनी, श्रेया यादव और नवीन
डालविल की मृत्यु हुई थी। सबसे औरत नवीन
यह था कि बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी के रूप
में हो रहा था, जबकि उपलब्ध दस्तावेजों के
अनुसार उसे पार्किंग और स्टोरेज के लिए
इस्तेमाल किया जाना था। इससे भी अधिक
तिताजनक बात सामने आई-हादसे से लगभग
एक महीने पहले एक विद्यार्थी ने एमसीटी में
निकायत की थी। भारत में भवन निर्माण के
नियमों की कमी नहीं है। नक्शा स्वीकृत, भवन
उपविधियों, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा
अधिभाग प्रमाणपत्र, पार्किंग, बेसमेंट के उपयोग-
ह संख्या के लिए नियम हैं। लेकिन समस्या नियमों
की संख्या नहीं, उनके पालन की ईमानदारी है
जब किन्हीं भवन में एक मजिल की अगमति हो

और चार-पांच मजिलें खड़ी हो जाएं, जब बेसमेंट स्टोरेज के लिए स्वीकृत हो और वल्लभरी या व्यावसायिक गतिविधि चलने लगे जब सड़क की जलनिकासी बाधित हो और फिनिशिंग भी निर्माण चलता रहे-तो सवाल केवल नागरिक की मन्मथानी का नहीं है। सवाल उस पूरी निगरानात्मक व्यवस्था का है, जो आँखों के सामने होने वा बदलाव को देखने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं करती। भ्रष्टाचार केवल रजिस्ट्रार लेने का नहीं है। भ्रष्टाचार वह भी है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्य को जानबूझकर न निभाए।

हादसे के बाद
जीव का आश्वासन
पर कब होगी
जिम्मेदारी तय ?

लिब्रेरी (बाग़तपुरा)

बेसमेंट में
लगावैरी धक्का
मैर-कानूनी है

सुरक्षित शहर | सुरक्षित छात्र | विकसित भारत

दुर्घटना के बाद नहीं, दुर्घटना से पहले कार्रवाई हो।

किसी अवैध निर्माण को देखकर आंखें बंद क
लेना भी व्यवस्था के प्रति अपराध है। किसी भव
को जोखिमपूर्ण जानते हुए कार्रवाई न करना भ
भ्रष्ट प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा है।

आदमी किस पर भरोसा करे? मेरे 2024 : दिल्ली के आईटीओ स्थित सेंट्रल रैवेन्यू बिल्डिंग में आग लगी थी। 46 वर्षीय ऑफिस सुपरिटेण्डेंट की धुएं में दम घुटने से मृत्यु हुई थी। रिपोर्टों में अनुसार आग पुराना था और उसमें आधुनिक फायर-रिस्कलर व्यवस्था भी नहीं थी। यह घटना एक और सवाल सामने रखती है-जब सरकारें भवनों में भी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, तब निजी और अनधिकृत भवनों की निगरानी की स्थिति क्या होगी? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु और देश के अन्य महानगरों में अनियोजित शहर विस्तार लगातार बढ़ रहा है। जमीन सीमांत भू-जनसंख्या बढ़ रही है, किराये की मांग बढ़ रही है और व्यावसायिक हित अधिकतम जगह को

अधिकतम उपयोग चाहते हैं। ऐसे में यदि शासन मजबूत नियमन और वैज्ञानिक शहरी नियोजन नहीं करेगा तो शहर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा नीचे गिरती जाएगी। दुर्घटना के बाद वही परिचित दृश्य सामने आता है—मंत्री घटनास्थल पर पहुंचते हैं, अधिकारी बैठक करते हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, जांच समिति बनती है, कुछ भवन समित होते हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं और कुछ दिनों तक प्रशासन सक्रिय दिखाई देता है। फिर धीरे-धीरे सब सामान्य हो जाता है। लेकिन किसी मृत विद्यार्थी के माता-पिता के लिए कुछ भी सामान्य नहीं होता। उनके लिए वह एक जांच समिति नहीं, जीवनभर का खालीपन है। उनके लिए मुआवजे की राशि उनसे बटे या बेटी का विकल्प नहीं है। वे यह जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित क्यों नहीं था? किसने सुरक्षा की गारंटी दी थी? किसने निगरानी की थी? किसने खरटे को नजरअंदाज किया था? इसलिए जांच का उद्देश्य केवल दोषी व्यक्ति ढूँढना नहीं होना चाहिए। जांच को यह भी पता लगाना चाहिए कि किस स्तर पर सिस्टम विफल हुआ। फाइल कहाँ रुकी? निरीक्षण किसने किया? शिकायत किसने दबाई? नक्शा किस आधार पर स्वीकार हुआ? अवैध निर्माण वर्षों तक कैसे चलता रहा? भवन में रहने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तब होगी जिनकी जिम्मेदारी ही ऐसे

हादसों को रोकेना थी? सत्यनिकेतन के मलबे से आज देश को केवल छह मीतों का आंकड़ा नहीं देखना चाहिए। वहां दबे हुए सपनों को देखना चाहिए। उन माता-पिताओं की आंखों को देखना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली भेजते समय यह सोचा होगा कि वे पहुँचें, अगर बहुतेँ और परिवार का नाम रोशन करेंगे। उन सपनों की मौत केवल एक इमारत के गिरने से नहीं हुई है, वे उस मानसिकता के नीचे दबे हैं जिसमें नुयमों से अधिक प्रभावशाली पैसा, सुविधा और 'सब चलता है' की संस्कृति बन जाती है। अब समय है कि सहराँ हादसों के बाद जागने की आदत छोड़ें। भवन गिरने से पहले निरीक्षण हो, पानी भरने से पहले जलनिकासी सुधरे, शिखारत मिलने से पहले कार्रवाई हो और भूधराचल देश से पहले ही उसकी गुराँइश बंद हो। क्योंकि हादसे को केवल नया भारत नहीं बनाना है-उसे सुरक्षित, जिम्मेदार, ईमानदार और संवेदनशील भारत भी बनाना है। सत्यनिकेतन का मलबा इतने से यही पूछ रहा है-अगली इमारत गिरने का हतजात्र करेगी या अब व्यवस्था को समझ जगाएंगे?

सू- दोक् क्र.154

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 9 वर्गों का एक खंड बनता है।

2. हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते हैं।

3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोक् क्र.153 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1

शब्द सामर्थ्य -154

आएँ से द्वाएँ

1. दुहुरी पर के बाल, दुहरी, ठोड़ी
3. विरोध और सामाज्य (आन्दोलन), आम और खास लोग (ब.) 5.
- इन्चा, हस्तार, अभिलाशा 6.
- साविकी कोलारवा, मुकुमारता (ब.) 7.
- सविनय, निन्ता पूर्वक
10. बिलख-बिलख कर रोना 11.
- कहानी, उपन्यास 12. कुशल, स्व.
- निरोपत्र 13. भार, दबाव 14. शुभ-

अशुभ की पूर्व सूचना, शुभ अवसर पर होने वाला मंगल कार्य संबंधी गीत 15. एहसास, फिल, हिल 17.

सुल काटने, लपेटने में काम आने वाली पच्चेसी से लगी सराई 19. एक हिन्दी महीना, अग्रण 20. साहज का एक हिंदू, चूहमस्तिनास

ऊपर से नीचे

1. जंगल में लगी आम, दागीर्ण 2.
- मूल्य, दाम 4. स्वामी, स्वामीणी 5.

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 153 का हल

ख	प	ख		इ					
स	ह	व	र	सा	त			प	
क	हा	नी	न	क	च	डा			
त			ख	ली	री	ई			
क	या	म	त	क	फ	न			
दी	दी	या	वू		ह	वा			
र	हा	न	ल	त	खो	र			
ह	या	नी	क						
भा	ई		का		या	द	ल		

संकट, कष्ट, दर्द 7. लकड़ी, कच्चा, कच्ची में पहचाने का उपकरण, श्रेय 8.

बैद्यनाथी, आन्दार 9. शो 10. मुरंता, बसंत ऋतु 10. लबाव करने वाला, विनासक 11. दश सप्तय 13.

अनुर, रासना, हिल 14. वृ, मुसल काटने अथवा धुलने 15. पूर्व, लीला 16.

शिवयंत्र, दृष्टान्त, पत्थन 17. वृष, पं. 18. मुष्ट से निकलने वाला 19. सूख लीला पत्थर 19.

एक

नजर

राज्य स्तरीय जुड़ो प्रतियोगिता में लवकुश ने जीता स्वर्णपदक



भिलाई, 8 सितम्बर। जनता शिक्षण समिति द्वारा संचालित जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा नवमी के छात्र लवकुश शर्मा ने राज्य स्तरीय जुड़ो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 किलोग्राम वजन वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। लवकुश की सफलता पर विद्यालय के प्राचार्य अरुण कुमार ने उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत करते हुए सौचकल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छात्र की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए निरंतर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन ने विश्वास जताया कि लवकुश भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय, प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करेंगे।

ब्रह्माकुमारी संस्थान ने नशे के दुष्प्रभावों से कारणा अवगत,ध्यान से तनाव नियंत्रण का दिया संदेश

बीजापुर, 8 सितंबर । जिले में ब्रह्माकुमारी संस्थान के तत्वावधान में स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में जागरूकता अभियान को बढ़ावा देते हुए सोमवार को लोहाडोंगरी प्रांगण में डीआजी जवानों के साथ नशामुक्ति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जवानों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागस्क करना तथा तनावपूर्ण परिस्थितियों में मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रहने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यशाला के दौरान ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रतिनिधियों ने नशे के विभिन्न प्रकारों और इसके सेवन से होने वाली शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि नशे की आदत व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके परिवार और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। नशे से दूर रहने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, सकारात्मक सोच और अनुशासित दिनचर्या को महत्वपूर्ण है । कार्यशाला में जवानों को योग एवं ध्यान के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। विशेष रूप से राजयोग एवं ध्यान के माध्यम से तनाव नियंत्रण, मानसिक शांति और आत्मसंयम विकसित करने के उपाय बताए गए। जवानों को समझाया गया कि नियमित ध्यान और सकारात्मक चिंतन तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने में सहायक हो सकता है।

भाजपा पश्चिम नगर मण्डल स्तरीय सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला आयोजित

जगदलपुर, 8 सितंबर। जिला भाजपा पश्चिमी नगर मण्डल द्वारा आज सोमवार को सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला का आयोजन भायक्षा जिला कार्यालय में किया गया। भारतीय जनता पार्टी आगामी 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। जिसमें एक माह तक विविध कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ता जनता के मध्य पहुंच कर पूरे करेंगे।कार्यशाला को संबोधित करते हुये मुख्य वक्ता बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवा के सफलतम 25 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा सेवा संकल्प अभियान मनाया जायेगा। जिसमें राष्ट्रीय स्तर से बृथ स्तर तक कार्यक्रम पूरे होंगे। भाजपा का लक्ष्य कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। भाजपा के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ता आम जनता से जुड़ कर कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक संपन्न कराएंगे। श्री कश्यप ने सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी।भाजपा जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पाण्डेय ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिसमें भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी सहभागिता निभानी है। जनता की सेवा से जुड़े विविध तरह कार्यक्रम को रूपरेखा बनायी गयी है, जिसे साकार रूप दिया जायेगा। मण्डल प्रभारी सफीरा साहू और पश्चिमी मण्डल अध्यक्ष प्रकाश झा ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।

कलेक्टर की अभिनव पहल से अब अंतागढ़ में ही मिलेंगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं

कांकेर, 8 सितम्बर । जिले के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र अंतागढ़ एवं कोयलीवेड़ा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अब बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने महत्वपूर्ण पहल की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अंतागढ़ के ऑपरेशन थिएटर को शीघ्र रूप से क्रियाशील करने के साथ ही यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इससे क्षेत्र के मरीजों को उपचार एवं ऑपरेशन के लिए जिला मुख्यालय अथवा अन्य शहरों तक लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम होगी। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने आज दंडकवन एवं धन्वंतरी सेवा समिति से संबद्ध चिकित्सक डॉ. आनंद जोशी एवं उनकी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अंतागढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में उपलब्ध सुविधाओं, आवश्यक उपकरणों तथा अन्य संसाधनों का बारीकी से जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी दो सप्ताह के भीतर ऑपरेशन थिएटर को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पावर बैकअप, ऑक्सीजन पाइपलाइन सहित ऑपरेशन के लिए आवश्यक सभी संसाधनों की उपलब्धता प्राथमिकता से सुनिश्चित करने कहा। साथ ही ऑपरेशन सेवाओं के लिए आवश्यक चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं अंतागढ़ में उपलब्ध कराने के संबंध में डॉ. जोशी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सोनोग्राफी एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट की सुविधा प्रारंभ करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

प्रादेशिकी

तरुण छत्तीसगढ़

बारिश में बेरोदी नदी का जलस्तर बढ़ते ही 11 गांवों का कट जाता है संपर्क

पुल न होने से मरीजों का अस्पताल,बच्चों का स्कूल जाना हो जाता है मुश्किल

राजकुमार कोण्डगुरला

बीजापुर 8 सितम्बर। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी, लेकिन विकास की तस्वीर ऐसी कि बारिश आते ही पूरा इलाका मुख्यधारा से कट जाता है। कोटेर-पदमुर क्षेत्र के 11 से अधिक गांवों के लिए बेरोदी नदी अब महज नदी नहीं, बल्कि विकास और जिंदगी के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। बारिश में जलस्तर बढ़ते ही गांवों का संपर्क टूट जाता है और मरीजों से लेकर स्कूली बच्चों तक को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। इसी गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर विश्वदीप को ज्ञापन सौंपकर बेरोदी नदी पर स्थायी पुल निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से समस्या झेल रहे हैं, लेकिन हर बरसात में वही संकट फिर सामने खड़ा हो जाता है।

बारिश आई, तो गांव बन जाते हैं टापू

कोटेर, पदमुर, मौसला, कैका, दुखा, कचीलवार, गुंडापुर, चेरकटी, जासोया और कडेनार समेत आसपास के गांवों में बारिश के दिनों में आवागमन सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। नदी में पानी बढ़ते ही मुख्य मार्ग से संपर्क टूट जाता है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि नदी पार करना तो दूर, उसके करीब जाना भी



खतरे से खाली नहीं रहता।

मरीजों के लिए नदी बनी जिंदगी-मौत का सवाल

सबसे गंभीर स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि नदी पार करना तो दूर, उसके करीब जाना भी

हादसे का कारण बन सकता है।

धान बेचने से खाद-बीज तक हर काम पर पहरा

किसानों की परेशानी भी कम नहीं है। ग्रामीणों सुरेश वर्मा, राम सिंह वर्मा और बुच्चैया पसपुल ने बताया कि धान बेचने, खाद-बीज खरीदने और कृषि से जुड़े जरूरी कामों के लिए नदी पार करना मजबूरी है। जलस्तर बढ़ने पर कई

नशे के खिलाफ डीआरजी जवानों ने भरी हुंकार

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बीजापुर, 8 सितंबर। नक्सल मोर्चे पर मुस्लेदी से डटे छत्र जवान अब नशे के खिलाफ भी जागरूकता की मुहिम का हिस्सा बने। सोमवार को लोहाडोंगरी प्रांगण में ब्रह्माकुमारी संस्थान के तत्वावधान में जवानों के लिए नशा मुक्ति जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों और इससे होने वाले नुकसान को लेकर जवानों को विस्तार से जानकारी दी गई।

नशा सिर्फ शरीर नहीं, पूरा परिवार तोड़ता है

कार्यशाला में नशे के विभिन्न प्रकारों और इसके कारण होने वाली शारीरिक एवं मानसिक क्षति के साथ पारिवारिक कहल, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट और आर्थिक



नुकसान जैसे गंभीर प्रभावों पर चर्चा की गई। जवानों को समझाया गया कि नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने के लिए इच्छाशक्ति के साथ सकारात्मक सोच और अनुशासित दिनचर्या बेहद जरूरी है। राजयोग बना तनाव से लड़ने का हथियार-ड्यूटी के दौरान तनाव और

मानसिक दबाव से निपटने के लिए जवानों को राजयोग एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। मानसिक शांति, आत्मसंयम और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए योग-ध्यान तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया गया। जवानों ने लिया नशामुक्ति का

गीदम में विकास कार्यों को मिली गति, मूलभूत सुविधाओं को पहली प्राथमिकता:रजनीश सुराना

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 8 सितम्बर । नगर पंचायत गीदम में विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से गति दी जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष रजनीश सुराना के नेतृत्व में मूलभूत सुविधाओं को पहली प्राथमिकता देते हुए सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़े कार्यों के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े एवं स्थायी विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर में लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से नालंदा परिसर, लगभग सवा करोड़ रुपये की लागत से मटन मार्केट, मुक्तिधाम के पुनर्विकास, वार्ड क्रमांक 12 में महिला जिम, विभिन्न वार्डों में सड़क एवं नाली निर्माण तथा नगर के सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर कार्य आगे बढ़ रहा है। वहीं पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगभग 90 लाख रुपये की राशि सम्मलेल एवं राइजिंग मेन के लिए स्वीकृत हो चुकी है और इसका टेंडर भी हो चुका है।

बारिश के कारण नगर के विभिन्न वार्डों के मुख्य एवं प्रमुख मार्गों पर हुए छोटे-बड़े गड्ढों को भरने का कार्य नगर पंचायत द्वारा आज से प्रारंभ किया गया। नगर पंचायत की टीम विभिन्न वार्डों में गड्ढों को चिह्नित कर उन्हें भरने का कार्य कर रही है। पार्षद भी अपने-अपने वार्डों में आवश्यक स्थानों को चिह्नित कराने एवं कार्य में सहयोग कर रहे हैं। गीदम के मुख्य NH मार्ग पर बारिश के बाद बड़ी संख्या



में गड्ढे हो गए थे, जिससे राहगीरों एवं वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी के साथ दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। जनहित को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष रजनीश सुराना के नेतृत्व में नगर पंचायत के कर्मचारियों, पार्षदों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से मुख्य NH मार्ग के गड्ढों को भरने का कार्य भी किया जा रहा है। इस अभियान में नगर पंचायत अध्यक्ष रजनीश सुराना के साथ पार्षद सूरज ठाकुर, अवधेश गुप्ता, खिलासन सागर एवं श्रीकांत राव, नेता प्रतिपक्ष सोहन यादव सहित वरिष्ठ नागरिक मस्किराजुन राव, रमेश डगगा एवं गोलू यादव, पूर्व पार्षद सुनील गोल्लेख, मनीष पांडे सहित नगर पंचायत के कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिकों ने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई। नगर पंचायत अध्यक्ष रजनीश सुराना ने सभी जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों, नगर पंचायत कर्मचारियों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर के विकास और जनहित के कार्यों में सभी का सहयोग मिलना सकारात्मक

और उत्साहजनक है। जब जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और नागरिक मिलकर किसी समस्या के समाधान के लिए आगे आते हैं, तो उसका सकारात्मक परिणाम सामने आता है।-उन्होंने कहा कि बारिश के कारण कई मार्गों पर गड्ढे हो गए थे, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी के साथ दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई थी। लोगों की शिकायत का इंतजार किए बिना नगर पंचायत ने स्वयं इसका संज्ञान लेकर तत्काल गड्ढे भरने का कार्य शुरू किया है। इसी प्रकार खराब नालियों के निर्माण एवं सुधार के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं। स्वीकृति प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता और शासन का पैसा महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसी जगह राशि खर्च करने की प्राथमिकता है, जहां उसका स्थायी लाभ नगरवासियों को मिल सके।

पानी की समस्या के स्थायी समाधान की ओर कदम

गीदम में पेयजल समस्या के स्थायी



दिनों तक आवागमन ठप हो जाता है, जिससे खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित होते हैं।

स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों की 'जल परीक्षा'

बेरोदी नदी का सबसे बड़ा खामियाजा स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पुनेश समतुल और महादेव गोंगला ने बताया कि जुलाई से दिसंबर तक नदी में पानी और बाढ़ के कारण स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कई बार शिक्षक भी जोखिम उठाकर नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं। तेज बहाव के बीच बच्चों का नदी पार करना किसी बड़ी अनहोनी को न्योता देने जैसा है।

लाल आतंक से बाहर आया क्षेत्र, अब विकास की बारी

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र लंबे समय

तक लाल आतंक के साये में रहने के कारण विकास की मुख्यधारा से दूर रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर बसे गांवों को स्थायी आवागमन सुविधा से वंचित रखना बड़ा सवाल खड़ा करता है।

पुल नहीं तो हर बरसात यही कहानी!

बेरोदी नदी पर स्थायी पुल निर्माण अब ग्रामीणों के लिए सुविधा नहीं बल्कि जरूरत और सुरक्षा का सवाल बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तत्काल बड़े पुल का निर्माण संभव नहीं है तो ऋष्ट पुलिया अथवा फ्लश कॉजवे जैसे व्यवहारिक विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

पूर्व में भी तरुण छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा पुल की समस्या पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया गया था लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। अब देkhना होगा कि जिला मुख्यालय के इतने करीब होने के बावजूद इन गांवों तक विकास की राह कब पहुंचेगी? क्या हर साल बारिश में ग्रामीणों को इसी तरह जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करनी पड़ेगी, या प्रशासन अब बेरोदी नदी पर स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएगा?

समाचार

संक्षेप

साइबर ठगों से बचने छात्राओं को किया अलर्ट



बीजापुर, 8 सितंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता) । मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर ठगी के खतरे को देखते हुए बीजापुर पुलिस ने अब महिलाओं और छात्राओं को साइबर अपराधियों के निशाने से बचाने के लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 'साइबर जागृति अभियान' के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चौथे सप्ताह महिलाओं, बच्चों और छात्राओं को केंद्रित कर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 176 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्रामीण महिलाओं और स्कूली छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों के नए-नए तरीकों से अवगत कराते हुए उनसे बचाव के उपाय बताए गए। पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं को फर्जी कॉल, OTP ठगी, ATM एवं UPI फ्राड, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया अपराध, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे अपराधों के प्रति विशेष रूप से सतर्क किया। पुलिस ने साफ संदेश दिया कि साइबर अपराधी छोटों सी लापरवाही का फायदा उठाकर लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं।जागरूकता कार्यक्रमों में नागरिकों को समझाइश दी गई कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, ATM PIN, CVV, UPI PIN, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने और किसी के कहने पर ऑनलाइन लेन-देन करने से भी बचने की सलाह दी गई। साइबर ठगी का शिकार होने की स्थिति में समय गंवाए बिना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी। बीजापुर पुलिस का यह अभियान खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने, जानकारी साझा करने से पहले सोचने और साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत करने की अपील की है।

नकली गड़ड़ी बेचने के मामले में कार्रवाई

दुर्ग, 8 सितंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता) । दुर्ग के इंदिरा मार्केट में नामी ब्रांड टाइटन और फास्टेक के नाम पर नकली घड़ियां बेचने के आरोपों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है दुर्ग सिटी कोतवाली थाने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान चलाकर कमलेश निर्मलकर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आरोपी की दुकान से बड़ी संख्या में नकली घड़ियां और अन्य सामग्री बरामद की है टाइटन कंपनी की ओर से ब्रांडेड घड़ियों की असली-नकली जांच और कार्रवाई के लिए अधिकृत गौरव तिवारी ने दुर्ग सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी शिकायत में बताया गया कि इंदिरा मार्केट स्थित सत कबीर वाच का संचालक लंबे समय से टाइटन और फास्टेक के नाम और ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नकली घड़ियां बेच रहा है, तलाशी के दौरान टाइटन और फास्टेक की 280 नकली घड़ियां, फास्टेक के 275 नकली टैग और आरोपी का मोबाइल फोन बरामद किया गया दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया की आरोपी नकली घड़ियों को असली ब्रांड का बताकर ग्राहकों को बेचता था और इसी के जरिए अवेध मुनाफा कमाता था। मामले में कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 और बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।उन्होंने ने लोगों और व्यापारियों से अपील की है कि ब्रांडेड सामान खरीदते समय उसकी प्रामाणिकता जरूर जांचें और नकली सामान की बिक्री की सूचना तत्काल पुलिस को दें

सांसद महेश कश्यप की पहल से एलपीजी सिलेंडर का

45 दिन का इंतजार खत्म,अब 25 दिन में होगी बुकिंग

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 8 सितंबर । दंतेवाड़ा जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के लिए निर्धारित 45 दिनों की अवधि को घटाकर 25 दिन करने की मांग को लेकर बस्तर सांसद महेश कश्यप द्वारा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर व्यवस्था में सुधार की मांग की गई थी। सांसद की पहल के बाद अब केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इंडियन ऑयल,भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को निर्देशित किया गया है कि घरेलू एलपीजी रिफिल की बुकिंग के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से 25 दिनों का अंतर निर्धारित किया जाए। यह व्यवस्था



केंद्रीय मंत्री को भेजे पत्र में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों की बुकिंग अवधि से आम उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि कई परिवारों में एक गैस सिलेंडर 25 से 30 दिनों में समाप्त हो जाता है, लेकिन 45 दिनों की बाध्यता के कारण उपभोक्ताओं को सिलेंडर समाप्त होने के बाद कई दिनों तक परेशानी उठानी पड़ती है। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा सहित बस्तर के

लोगों की सुविधा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एलपीजी बुकिंग की अवधि को 45 दिन से घटाकर 25 दिन करने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 25 दिन का समान अंतर लागू करने का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनसुविधाओं को बेहतर बनाने और आम नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाओं में सुधार के लिए लगातार कार्य कर रही है। जनता की समस्या को उठाना और उसका समाधान सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।

151 गुम मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को सुर्पुर् किए गए

कोंडागांव, 8 सितंबर। जिले की पुलिस द्वारा गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस की तकनीकी टीम ने लगातार प्रयास करते हुए कुल 151 गुम मोबाइल फोन बरामद किए। मोबाइल फोन की तलाश के दौरान तकनीकी माध्यमों से उनकी जानकारी एवं उपयोग के स्थानों का पता लगाया गया। कई मोबाइल फोन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों तथा सीमावर्ती राज्यों में उपयोग किए जा रहे थे। संबंधित स्थानों पर समन्वय स्थापित कर पुलिस द्वारा इन मोबाइलों को बरामद किया गया। बरामद किए गए मोबाइल फोन पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा द्वारा आज सोमवार को उनके वास्तविक मालिकों को सुर्पुर् किए गए।

कोंडागांव एसपी पंकज चन्द्रा



ने नागरिकों को ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम-डेबिट कार्ड की जानकारी, पासवर्ड एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने तथा फर्जी केवायस अपडेट, बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कस्टमर केयर, डिजिटल

अरेस्ट एवं अन्य प्रकार की ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए जागरूकता और सतर्कता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो बिना समय गंवाए तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें तथा नजदीकी पुलिस थाना को भी सूचना दें। पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान यह संदेश देता है कि मोबाइल गुम होने के बाद उसे वापस पाने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पुलिस की तकनीकी टीम द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर मोबाइल को ट्रेस करने का लगातार प्रयास किया जाता है।

एक

नजर

समान नागरिक संहिता की ड्राफ्टिंग छत्तीसगढ़ में तेज

रायपुर,8 सितंबर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को व्यावहारिक, समावेशी और जन-उपयोगी बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा गठित CC समिति ने जन-पारामर्श और विचार-विमर्श की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सेवानिवृत्त आईएसएस अधिकारी श्री एम. के. राजत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या श्रीमती ज्योति रानी सिंह के समक्ष विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए कुलपति ने खुलकर अपनी राय रखी। बैठक में पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं से लेकर आधुनिक वैधानिक सुधारों तक के कई अहम पहलुओं पर गहन मंथन हुआ। बैठक के दौरान प्रदेश के प्रमुख शिक्षाविदों और कुलपति ने कानून निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें CC समिति ने ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता से शामिल करने का आश्वासन दिया है। देश के प्रतिष्ठित विधिक संस्थानों में शामिल हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंदन ने पावर पाईट प्रजेन्टेशन देकर समान नागरिक संहिता के संबंध में विस्तृत सुझाव दिए। उन्होंने एक मजबूत, निष्पक्ष और न्यायसंगत मसौदा तैयार करने के लिए हर संभव तकनीकी और कानूनी सहयोग देने के लिए हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिबद्धता जताई। एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसे नियम तय करता है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना और विशेषकर महिलाओं के लिए न्याय व समानता सुनिश्चित करना है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने ड्राफ्ट को शोध-आधारित बनाने के लिए समाजशास्त्र, मानवशास्त्र तथा विधि विभागों के विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं के इनपुट्स को शामिल करने पर बल दिया। प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक जमीनी सर्वे कराने और आम जनता से सीधे प्रतिक्रिया (जन-फीडबैक) लेने का सुझाव दिया गया, ताकि कानून राज्य की वास्तविक परिस्थितियों और जन-आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार हो सके। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल ने भी इस संबंध में सुझाव दिए।

हरियाली के साथ ग्रामीणों को रोजगार की नई राह दे रहा विकसित भारत जैरामजी

रायपुर, 8 सितंबर। विकसित भारत - जैरामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री श्री गिष्णु देव साय के नेतृत्व में यह ग्रामीण परिवारों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित कर रही है, जो भविष्य में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसी सोच का प्रभाव कोड्डागांव जिले के जनपद पंचायत बड़ेराजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बीोपारा के आश्रित ग्राम बावनपुरी में देखने को मिल रहा है। यहां समुदाय के लिए पॉकबन्ड मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के तहत 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,500 पौधों का रोपण किया गया है। इस कार्य के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को क्रियाव्यवण एजेंसी बनाया गया है। बावनपुरी में संचालित वृक्षारोपण परियोजना के तहत लगभग 11 लाख रुपए की लागत से 2,667 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। ग्रामीण श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर आय का साधन मिला है और रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी मदद मिल रही है। यह कार्य इस बात का उदाहरण है कि ग्रामीण रोजगार से जुड़े कार्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ जोड़कर एक साथ रोजगार, पर्यावरण और आजीविका को मजबूती दी जा सकती है। मिश्रित वृक्षारोपण के अंतर्गत 13 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। आने वाले वर्षों में इनके वृक्ष का रूप लेने से क्षेत्र में हरियाली का विस्तार होगा। साथ ही वृक्षारोपण मिट्टी एवं जल संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में भी सहायक होगा। पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन में ग्राम बावनपुरी की संयुक्त वन प्रबंधन समिति भी जनभागीदारी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुफ्त बिजली योजना से सरगुजा में बढ़ रही ऊर्जा आत्मनिर्भरता

रायपुर, 8 सितंबर। प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना सरगुजा जिले में परिवारों को बिजली खर्च से राहत देने के साथ उन्हे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। घरों की छतों पर स्थापित सूर्योप सौर संयंत्र अब केवल घरेलू बिजली की जरूरत पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिताही अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर विद्युत ग्रिड में भी योगदान दे रहे हैं। अभिवक्ता विकासखंड के ग्राम पंचायत आमरदरहा निवासी श्री आलम साय रजवाड़े इसकी प्रेरणादायी मिसाल हैं।

श्री आलम साय ने अपने घर की छत पर प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर संयंत्र स्थापित करवाया। उन्होंने बताया कि संयंत्र लगने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 1,500 से 2,000 रुपये तक



आता था। सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू होने के बाद पिछले लगभग साढ़े तीन महीने से उनका बिजली बिल शून्य है। इससे परिवार के मासिक खर्च में उल्लेखनीय राहत मिली है।

श्री आलम साय कहते हैं, «पहले मैं बिजली उपभोक्ता था, लेकिन अब बिजली दाता बन गया हूं।» उन्होंने बताया कि सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली से पहले घर की जरूरत पूरी होती है और इसके बाद

श्री आलम साय ने बताया कि सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की सहायता प्राप्त हुई। इस तरह कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी मिलने से सोलर संयंत्र स्थापित करने का आर्थिक भार काफी कम हुआ। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदन से लेकर संयंत्र स्थापना तक की प्रक्रिया सुविधाजनक रही। योजना से मिले लाभ से उत्साहित श्री आलम साय ने अन्य पात्र बिजली उपभोक्ताओं से भी प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने की अपील की।

श्री आलम साय ने कहा, मेरा बिजली लाल लगभग साढ़े तीन महीने से शून्य है। योजना का मुझे बहुत फायदा मिला है और मैं इससे बहुत खुश हूं।

सिविल अस्पताल कुरुद को अब विधायक की सीधी मॉनिटरिंग की दरकार

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

कुरुद 8 सितंबर। वर्ष 1952 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में शुरू हुई कुरुद की स्वास्थ्य सेवाएं आज 100 बिस्तर वाले आधुनिक अस्पताल की ओर बढ़ रही है। इस लंबे सफ़र में क्षेत्र के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर की भूमिका को क्षेत्रवासी महत्वपूर्ण मानते हैं। जब छत्तीसगढ़ अभिजात मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उस समय से ही वे कुरुद विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाले सिविल अस्पताल कुरुद को अब मॉनिटरिंग का मरहम चाहिए।

कुरुदक्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी उम्मीद माने जाने वाला सिविल अस्पताल कुरुद लंबे समय से कभी चिकित्सकों की कमी, कभी विशेषज्ञ सेवाओं, कभी जांच सुविधाओं तो कभी संसाधनों को लेकर समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है। अस्पताल का विस्तार 100 बिस्तरों



की दिशा में हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि विस्तर बढ़ने के साथ क्या स्वास्थ्य सुविधाएं भी उसी अनुपात में बढ़ेंगी, यही सवाल आज कुरुद की जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुरुद विधानसभा के विधायक एवं प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और अस्पतालों की जमीनी जरूरतों से भली-भांति परिचित हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की अपेक्षा

है कि वे समय-समय पर सिविल अस्पताल कुरुद की सीधी मॉनिटरिंग और समीक्षा करें। जनप्रतिनिधि की सक्रिय निगरानी से अस्पतालों की व्यवस्थाओं में जवाबदेही बढ़ने के साथ-साथ छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान को भी गति मिल सकती है। सिविल अस्पताल कुरुद में प्रतिदिन बढ़ी संख्या में मरीज निश्चित रूप से स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन 100 बिस्तरों की क्षमता के अनुरूप चिकित्सक, विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ़ तकनीकी कर्मचारी, जांच सुविधाएं, दवाइयां और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। जनता का कहना है कि अस्पताल को केवल बड़ा भवन नहीं, बल्कि बेहतर इलाज की विश्वसनीय व्यवस्था चाहिए। यदि अभी से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयारी की जाए तो आने वाले समय में अस्पताल पर बढ़ने वाले मरीजों के दबाव को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता

है। सिविल अस्पताल कुरुद का नाम बार-बार समाचारों में आना इस बात का संकेत है कि यहां की समस्याओं पर लगातार चर्चा तो हो रही है, लेकिन अब जरूरत चर्चा से आगे बढ़कर स्थायी समाधान तक पहुंचने की है। अस्पताल से जुड़े विषयों की नियमित समीक्षा हो, अधिकारियों से जवाब-तलब हो और आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए शासन स्तर पर पहल हो—तो अस्पताल की तस्वीर में बड़ा बदलाव संभव है। (1)उतम साहू पार्षद नगर पालिका परिषद कुरुद कुरुद का सिविल अस्पताल हजारों लोगों की उम्मीद है। विधायक अजय चंद्राकर स्वयं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इसलिए उनसे अपेक्षा है कि वे अस्पताल की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा कर कमियों को दूर कराने की पहल करें। धनेश्वरी छव्व नागरिक 100 बिस्तरों अस्पताल बनना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ डॉक्टर और स्टाफ़की संख्या भी बढ़नी चाहिए। मरीजों को बेहतर इलाज मिले, यही असली उद्देश्य होना चाहिए। टोमन लाल सिन्हा ,मगरलेड क्षेत्रवासी ग्रामीण क्षेत्रों से

आने वाले मरीजों के लिए कुरुद सिविल अस्पताल बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ डॉक्टर, जांच और उपचार की सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध हों तो लोगों को दूसरे शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। (3) तुलेश साहू अस्पताल की समस्याएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। अब जरूरत ऐसी मॉनिटरिंग की है जिसमें समस्या सामने आने के बाद नहीं, बल्कि समस्या पैदा होने से पहले ही उसका समाधान सुनिश्चित हो। (4)जुमेश साहू पार्षद जनता की नजर अब मॉनिटरिंग पर कुरुद की जनता की अपेक्षा स्पष्ट है—अस्पताल का विस्तार केवल कागज और भवन तक सीमित न रहे, बल्कि हर मरीज को बेहतर और समय पर उपचार मिले। इसके लिए प्रशासनिक अमलें की जवाबदेही के साथ स्थानीय विधायकों की सक्रिय निगरानी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखना यह होगा कि सुर्खियों में रहने वाला सिविल अस्पताल कुरुद कब व्यवस्थाओं की मजबूती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुर्खियां बटोरता है।

तीज मिलन में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और मातृशक्ति का हुआ सम्मान



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

तिल्दा नेवरा/धरसीवा 8 सितंबर। विधानसभा के गांव सिलयारी में लोकसंस्कृति से जुड़ाव, मातृशक्ति का सम्मान और तीज की खुशियों का उत्सव मनाया गया। सिलयारी के मंडी प्रांगण में आयोजित भव्य तीज मिलन महोत्सव में छत्तीसगढ़ की जनप्रिय राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने मातृशक्ति एवं बहनों के स्नेह और आत्मीयता से यह आयोजन और भी यादगार बन गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल नितिन गोरीशंकर अग्रवाल सह-संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ रायपुर, जिला पंचायत सभापति श्रीमती सरोज चन्द्रवंशी , ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती गौरी साहू सभी मंडलों के मंत्राल अध्यक्षण, क्षेत्रीय नेतागण, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में देवतुल्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे। श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का छत्तीसगढ़ के तीज-त्योहारों और लोकपर्वों में निरंतर सहभागिता मातृशक्ति एवं प्रदेश की समृद्ध

तिल्दा विकासखंड में ‘जिस सरपंच की जितनी ताकत गांव में उतना विकास’

तिल्दा-नेवरा 8 सितंबर। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। तिल्दा विकासखंड में ग्रामीण विकास की तस्वीर कई सालों खड़े कर रही है। जनपद पंचायत का क्षेत्र दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों—बलौदा बाजार और धरसीवा—में बंटा होने के बीच गांवों में विकास का स्तर भी एक समान नजर नहीं आता। ग्रामीणों के बीच यह चर्चा आम है कि जिस सरपंच की जितनी राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़, उसके गांव में उतना ही विकास दिखाई देता है। विकास के दावों के बावजूद कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जुर्रा रहे हैं। कहीं जर्जर स्कूल भवन बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती हैं। कई स्थानों पर शौचालयों की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नाली और सफ़ाई व्यवस्था की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। गांवों की गलियों में जगह-जगह गंदगी और जलभराव की समस्या दिखाई देती है। वहीं कुछ गांवों में पीने के पानी की समस्या आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। गर्मों के दिनों में यह समस्या और गंभीर होने की बात ग्रामीण बताते हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है।



